दृष्टिकोण

भारत–चीन संबंध–4

चीन की चुनौती

भारत नीति प्रतिष्ठान

दृष्टिकोण

भारत-चीन संबंध-4

चीन की चुनौती

संपादक मंडल

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय
प्रो. सतीश कुमार
सतीश पेडणेकर
सौरभ ज्योति शर्मा

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी और ढंग से, प्रकाशक की पूर्व अनुमति के द्वारा नहीं किया जा सकता।

प्रकाशक :

भारत नीति प्रतिष्ठान

डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 (भारत)

दूरभाष : 011-26524018

फैक्स : 011-46089365

ई-मेल : indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org

संस्करण : प्रथम, जून, 2013

© भारत नीति प्रतिष्ठान

ISBN: 978-81-925223-2-6

मूल्यः 50 रुपये मात्र

मुद्रक :

पुष्पक प्रेस प्रा. लि.

203-204, डीएसआईडीसी शेड्स, ओखला फेस-1, नई दिल्ली

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन 4

अध्याय-एक

चीन के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध 5

अध्याय-दो

भारत चीन संबंधों की नई पड़ताल 10

अध्याय-तीन

भारत-चीन सीमा विवाद की पृष्ठभूमि 22

अध्याय-चार

चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए बहुआयामी खतरा 26

अध्याय-पांच

नेहरू की अदूरदर्शिता और चीन की मनमानी 30

अध्याय-छह

पर्यावरण की मार और घाटे का व्यापार 33

अध्याय-सात

पाक-चीन दोस्ती और अरूणाचल का संकट 36

अध्याय-आठ

नेपाल पर भी लगी है चीन की नजर 41

अध्याय-नौ

इतिहास के संदर्भ में भारत-चीन संबंधों की प्रमुख घटनाएं 45

प्राक्कथन

क्या चीन भारत के साथ सचमुच मित्रता चाहता है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि कम-से-कम वह दिखाना तो यही चाहता है। ऐसा स्थापित करने के लिए वह भारत के बुद्धिजीवियों, मीडिया एवं राजनीतिक दलों में अपनी छवि बना रहा है तो दूसरी ओर भारत के अरूणाचल, सिक्किम एवं लद्दाख पर भारत की संप्रभुता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

भारत ने पचास के दशक में पंचशील का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा था जिसका उद्देश्य भारत-चीन के बीच रचनात्मक संबंध स्थापित करना था। परंतु 1962 में चीन ने शक्ति प्रयोग से भारत के एक बड़े भू-भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तिब्बत पर उसका आधिपत्य संशयात्मक है। उसकी नई साम्राज्यवादी प्रक्रिया पंचशील के मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की नितान्त विरोधी है।

1962 से 2013 के बीच चीन के साथ भारत का व्यापारिक संबंध बढ़ा है तथापि चीन का आर्थिक हित भारत की तुलना में कई गुणा अधिक है। इस दौर में चीन ने सीमा विवाद को भी जीवित रखा है।

भारत की सीमा पर उसकी सैन्य तैयारी और कार्रवाई मित्रता का संकेत तो कम-से-कम नहीं देती है। तब भी चीन की कार्रवाई पर बौद्धिक विमर्श चीन के पक्ष में क्यों झुका होता है? यह प्रश्न विचारणीय है। चीन सरकार के निमंत्रण पर चीन जाने वाले बुद्धिजीवियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। चीन से उपकृत बुद्धिजीवियों के एक वर्ग का झुकाव चीन की तरफ देखा जा सकता है।

इन्हीं प्रश्नों पर भारत नीति प्रतिष्ठान निरंतर विमर्श एवं शोध करता रहा है। वर्तमान पुस्तिका इसी शृंखला का अंग है। इसके पहले भारत-चीन संबंध पर भा.नी.प्र. तीन शोध पुस्तिकाएं प्रकाशित कर चुका है। आशा है प्रतिष्ठान का यह प्रकाशन भारत-चीन संबंध पर और प्रकाश डालने एवं विमर्श करने के लिए प्रेरित करेगा।

प्रो. कपिल कपूर

अध्याय-एक

चीन के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे चरण के अंतिम वर्ष लद्दाख सीमा क्षेत्र में चीन की सेना के अतिक्रमण ने भारत-चीन संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी थी परंतु तनाव का यह दौर अधिक समय तक नहीं चल सका। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक चला यह तनाव विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा पर जाने से पहले ही इसलिए कम हो गया क्योंकि चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में गाड़े अपने तंबू उखाड़ लिए थे यह अलग बात है कि भारत सरकार को कुछ समझौते करने पड़े। सन् 2013 की इस घटना को लेकर देश का राजनीतिक पारा भी उछाल पर रहा। विपक्ष ने सरकार को जम कर कोसा और सरकार कई दिन तक बचाव की मुद्रा में रही परंतु आलम यह है कि ड्रैगन (चीन) अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और 17 मई, 2013 को श्रीजैप के प्रसिद्ध सिंगर-8 इलाके के पास चीन ने 5 कि.मी. अंदर तक भारतीय सीमा क्षेत्र में सड़क बना दी है और हाल ही में भारतीय सैन्य गश्ती दल को वास्तविक नियंत्रण रेखा तक नहीं जाने दिया। अखबारों के साथ ही इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपनी सुर्खियों में इसे जगह दी।

दरअसल हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत को चिढ़ाने की एक चीनी हरकत भर ही थी इसके अलावा कुछ नहीं। इससे पहले भी चीन कई बार कभी अरूणाचल के मुद्दे पर तो कभी सिक्किम के मुद्दे पर भारत को इस तरह की हरकतों से चिढ़ा चुका है। यद्यपि चीन को यह पता है कि भारत चाहते हुए भी चीन पर हमला करने की स्थिति में नहीं है और चीन के लिए भी 1962 की तरह अनुकूल स्थितियां नहीं हैं कि वो भारत पर हमला कर सके। चीन को यह भी पता है कि आज भारत न केवल ऐसे किसी सैन्य हमले का सफलता पूर्वक सामना करने की स्थिति में है बल्कि 1962 के मुकाबले आज भारत हर दृष्टि से अधिक मजबूत स्थिति में है। सच्चाई तो यह है कि चीन को भारत की सैन्य क्षमता का अहसास 1962 के युद्ध के ठीक पांच साल बाद 1967 में ही तब हो गया था

जब भारत ने चीन के एक ऐसे ही हमले का मुकाबला करते हुए उसके 400 सैनिकों को ढेर कर दिया था। चीन ने यह हमला सिक्किम की सीमा से लगे नाथुला क्षेत्र में किया था। यह खुलासा सामरिक विशेषज्ञ और भारतीय थल सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कर्नल अनिल भट्ट ने लोकसभा टीवी पर 17 मई, 2013 को प्रसारित एक कार्यक्रम में किया था। भारत चीन संबंधों की पड़ताल करने वाले इस कार्यक्रम में श्री भट्ट एक सैन्य विशेषज्ञ की हैसियत से बोल रहे थे। इस बाबत उनका यह भी कहना था कि इस घटना के बाद चीन को न केवल अपनी तथाकथित सामरिक क्षमता का अहसास हो गया था बल्कि उसे यह भी पता चल गया था कि भारत पर किसी तरह का हमला करना खुद उसके अपने वजूद के लिए नुकसानदायक साबित होगा। बहरहाल बदली आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक परिस्थितियों में चीन ने पैंतरा बदल कर भारत की अन्य तौर तरीकों से घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। इसमें कानूनी और गैरकानूनी दोनों तरीकों से भारत की आर्थिक नाकेबंदी के साथ ही भारत के पड़ोसी देशों को गुमराह कर उनके भू-क्षेत्रों का अपने हित में इस्तेमाल करना भी उसकी चाल है। चीन के नए नेतृत्व की इस भारत विरोधी रणनीति के चलते ही चीन ने पाकिस्तान से लेकर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया और म्यांमार तक लगभग भारत के सभी पड़ोसी देशों में अपनी गतिविधियों का संचालन करना शुरू कर दिया है। चीन के इन भारत विरोधी कारनामों के पीछे भारत-वियतनाम संबंध एक कारण हो सकते हैं परंतु भारतीय नेतृत्व की अदूरदर्शी विदेश नीति ने भी चीन को इस सीमा तक आगे बढ़ाने में मदद की।

भारत की सरकारों की ओर से बरती गई ढिलाई का ही नतीजा है कि भारत समेत जिन देशों की जमीन चीन ने 1962 के चीन-भारत युद्ध तक अपने कब्जे में कर ली थी उन्हें वह विवादित नहीं बल्कि अपनी जमीन मानता है चाहे वह तिब्बत और ताईवान हो या अन्य कोई और। इसके अलावा भारत समेत कई दूसरे देशों के एक बड़े भू-भाग पर भी उसकी नजरें गड़ी हुई हैं। भारत के कश्मीर, अरूणाचल और सिक्किम राज्यों के साथ ही पड़ोसी देशों के कुछ इलाकों पर भी उसकी नजरें टिकी हैं। चीन को यह अच्छी तरह मालूम है कि इन भू-भागों पर उसका कब्जा आसान काम नहीं है लेकिन समय-समय पर घुड़कियां देकर एवं असमंजस की स्थिति पैदा करके चीन इसकी याद जरूर दिलाता रहता है। लद्दाख के सीमा क्षेत्र में चीनी सैनिकों का तंबू गाड़ कर बैठना कुछ-कुछ इसी तरह की याद दिलाने की घटना का अहसास दिलाना है। पर भारत सरकार को चीन के नापाक इरादों को गंभीरता से लेना होगा और चीन के सीमा क्षेत्र में सैनिक चौकसी पर कड़ी नजर भी रखनी होगी।

1962 के चीन के अप्रत्याशित हमले का आघात न सह पाने के कारण जब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो गई तो चीन और भी उद्दंड हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत चीन की भारत संबंधी विदेश नीति में आक्रामकता आसानी से देखी

जा सकती है। यह बात अलग है कि 1967 में भारत से करारी मात खाने के बाद चीन की उद्दंडता उतनी आक्रामक नहीं रह पाई। भारत के प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार संजय बारू ने 25 मार्च, 2013 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने एक लेख के जरिए चीन की बदली नीति और नीयत पर सारगर्भित टिप्पणी की है। अपने इस लेख में संजय बारू ने यह खुलासा भी किया है कि 1962 के बाद की परिस्थितियों में चीन ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ हुए पंचशील के सिद्धांत की मूल भावना ही तोड़ खत्म कर दी है।

गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच पंचशील के सिद्धांत के अनुरूप हुए समझौते के तहत एशिया के इन दो बड़े देशों को एक-दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखते हुए पांच मुद्दों का सम्मान करना था। ये मुद्दे थे- (1) दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें। (2) एक दूसरे पर हमला न करें या एक दूसरे के प्रति आक्रामक न हों। (3) एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करें। (4) आपसी समानता और एक दूसरे के नफे नुकसान का ध्यान रखें और (5) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बनाए रखें।

संजय बारू आगे लिखते हैं कि चीन ने पहले तो 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील के इस सिद्धांत की मूल भावना ही खत्म कर दी थी और भारत-चीनी भाई-भाई के नारे पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया था। भारत के प्रति असहिष्णुता का यह सिलसिला चीन ने यहीं तक सीमित नहीं रखा बल्कि बाद के वर्षों में तो भारत को सबक सिखाने की गरज से चीन के नए नेतृत्व ने पांच के अंक का महत्व तो बरकरार रखा लेकिन पांचों सिद्धांतों की अपने अनुरूप व्याख्या कर सभी की नई परिभाषा भी गढ़ दी। चीन की नई सोच के अनुसार भारत-चीन संबंधों की मैत्री के पांच नए तत्व इस प्रकार हैं। (1) सामरिक या रणनीतिक संचार और स्वस्थ पारस्परिक संबंध (2) एक-दूसरे की ताकत को मजबूत बनाने के साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास में एक-दूसरे को सहयोग करना (3) सांस्कृतिक संबंधों में मजबूती और परस्पर दोस्ती तथा समझ विकसित करना। (4) विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा के लिए परस्पर सहयोग से बहुआयामी क्षेत्रों में सहभागिता के रास्ते की तलाश और (5) एक दूसरे के मूल सरोकारों की हिफाजत करते हुए परस्पर असहमति के मुद्दों का मिल बैठ कर समाधान करना। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि चीन की ओर से प्रस्तावित आपसी सहमति के इन पांच नए सूत्रों में भारत के लिए पहले चार सूत्रों पर समझौता करने में कोई अड़चन नहीं दिखाई देती क्योंकि बदली अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में पड़ोसी देश के साथ कुछ मुद्दों पर सहमति बनाना जरूरी भी हो जाता है और शायद इसीलिए पर्यावरण समेत तमाम मुद्दों पर भारत और चीन के बीच सहमति बनी भी है। इसका एक उदाहरण ब्रिक्स संगठन के रूप में ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ चीन का शामिल होना भी है। पर भारत को चीन के पांचवें

सूत्र पर स्वाभाविक रूप से आपत्ति है। वजह यह है कि इस सूत्र के तहत चीन ने अपने मूल सरोकारों को परिभाषित ही नहीं किया है। अगर हर परंपरागत रूप से देखें तो चीन के मूल सरोकार तो तिब्बत और ताईवान तक ही सिमट जाते हैं पर हाल के वर्षों में चीन के अधिकारियों ने दक्षिणी चीन सागर को अपने मूल सरोकारों के रूप में चिन्हित कर लिया है।

इस समुद्री क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक ऐसे द्वीप हैं जिन पर चीन ने अपना हक जताया है परंतु इन द्वीप समूहों को वियतनाम और फिलीपींस ने भी अपने नियंत्रण क्षेत्र में दर्शाया है। इस संबंध में भारत के प्रति चीन के दुराग्रह का एक बड़ा कारण यह भी है कि तेल के अथाह भंडार वाले इन द्वीपों में भारत भी गैस की कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

इस पूरे प्रसंग में भारत-चीन संबंधों के ऐतिहासिक परिवेश की व्याख्या करें तो भारत के प्रति चीन का यह रूख काफी चौंकाने वाला भी लगता है। इतिहास गवाह है कि भारत की आजादी के लगभग सवा दो साल बाद जब 1 अक्टूबर 1949 को चीन का वजूद सामने आया था तब एक गैर साम्यवादी देश के रूप में सबसे पहले भारत ने ही चीन को मान्यता दी थी तथा इसी के अनुपालन में 1 अप्रैल 1950 को भारत ने चीन की राजधानी पेइचिंग में अपना दूतावास खोला था। इसी के साथ भारत और चीन के कूटनीतिक (राजनयिक) रिश्तों की शुरुआत हुई थी। इसी आधार पर 1954 में पंचशील के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का पांच सूत्री समझौता भी हुआ था जिसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं और यह खुलासा भी कर चुके हैं कि आज किस तरह इस समझौते का अनादर करते हुए चीन अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति को अंजाम दे रहा है।

गौरतलब है कि भारत-चीन दोस्ती को सही मुकाम तक पहुंचाने की गरज से चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ-एन-लाई ने ही जून 1954 में भारत की यात्रा की थी। इसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी वर्ष 1 अक्टूबर को चीन की यात्रा पर गए थे। चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का यह सिलसिला यहीं पर नहीं रूका इसके बाद भी वे दो बार जनवरी 1957 और अप्रैल 1960 को भारत आए थे। चीन के प्रधानमंत्री के रूप में चाउ-एन-लाई की यह संभवतः अतिम भारत यात्रा थी। इसके दो साल बाद ही हिन्दी-चीनी भाई-भाई के तमाम रिश्तों को ताक पर रख कर चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच तमाम कूटनीतिक रिश्तों का अंत हो गया था।

लगभग तीन दशक बाद अगस्त 1976 में भारत-चीन संबंधों की एक नई शुरुआत हुई। एक बार फिर दोनों देशों ने अपने-अपने बंद दूतावासों से कामकाज शुरु किया। इस नई दोस्ती को रंगत दी 1979

में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा पर जाकर। अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के बाद चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री हुआंग हुआ भी जून 1981 में भारत की यात्रा पर आए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संबंध बहाली का सिलसिला भी शुरू हुआ। एक लंबे अरसे के बाद हुई संबंध बहाली को मजबूती देने की गरज से ही दिसंबर 1988 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी और एक संयुक्त कार्य समूह के साथ ही एक आर्थिक समूह का गठन भी हुआ।

परस्पर संबंधों के शुरुआती क्रम को जारी रखते हुए दोनों देशों के पदाधिकारियों ने आपसी राजनयिक यात्राओं का सिलसिला भी निरंतर जारी रखा। 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग और सितंबर 1993 में भारतीय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्ह राव की चीन यात्रा को भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है। नरसिम्ह राव की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) का सम्मान करने के बारे में सहमति बनी थी। अभी तक भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों ने ही एक दूसरे के देशों की यात्रा की थी, लेकिन मई 1992 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में आर. वेंकटरमन ने पहली बार चीन की यात्रा कर दोनों देशों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंधों के संकेत दिए थे। इन संबंधों को पुख्ता दिखाने की कोशिश में ही चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन भी नवंबर 1996 में पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे।

आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और एक दूसरे पर भरोसा जाहिर करने की गरज से भारत और चीन के नेताओं की यात्राओं का यह दौर आज भी बदस्तूर जारी है। 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बाद ऐसा लगने लगा था कि दोनों देशों के संबंधों में खटास आ जाएगी पर तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के चीन दौरे ने इस कुहासे पर से पर्दा हटाया। नतीजतन परस्पर आवागमन का यह सिलसिला बाद में भी जारी रहा और आज भी जारी है। भारत में संप्रग सरकार हो या राजग सरकार किसी भी सरकार ने भारत चीन संबंधों पर आंच तो नहीं आने दी लेकिन आपसी संबंधों की आड़ में चीन की विस्तारवादी और भारतीय हिस्से को अपना बनाने की चाल को भारत का कोई भी नेतृत्व नहीं समझ सका। भारत की इसी नासमझी को चीन ने अपना हथियार बना कर कभी कश्मीर, कभी अरूणाचल तो कभी सिक्किम के भारतीय क्षेत्र को अपना बनाने की मुहिम लगातार जारी रखी है।

अध्याय-दो

भारत चीन संबंधों की नई पड़ताल

2012 को भारत चीन युद्ध के 50 साल पूरे होते ही चीन ने एक बार फिर भारत को धौंस दिखाना शुरू कर दिया। अरूणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा न मान कर भारत के इस सीमावर्ती राज्य के लोगों को स्टेपल वीसा जारी करने, सिक्किम से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने का इरादा जाहिर करने और भारत के पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में रख कर इन देशों से भारत विरोधी हरकतों को अंजाम देने के साथ ही चीन ने 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत की शर्मनाक पराजय की याद दिलाते हुए एक बार फिर लद्दाख की सीमा के भीतर प्रवेश कर पांच सैनिक तंबू गाड़ कर भारत को संभवतः यह याद दिलाने की कोशिश की है कि सामरिक युद्ध में भारत आज भी चीन के सामने बौना ही है।

गौरतलब है कि पांच दशक की इस अवधि के दौरान तमाम तरह के सीमा विवादों के बाद भी भारत और चीन के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रि श्ते कायम होने के साथ ही जलवायु के मुद्दे पर दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुर में सुर मिलाने जैसी गतिविधियों के चलते यह भ्रम होना भी लाजिमी है कि कहीं भारत-चीन एक बार फिर पंचशील के सिद्धांत के अनुरूप हिन्दी-चीनी भाई-भाई का राग अलापना तो शुरू करने नहीं जा रहे हैं। पर वास्तव में स्थिति कुछ भिन्न है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने की गरज से दोनों देशों ने कई अवसरों पर हाथ तो जरूर मिलाए हैं पर दिलों का मिलन अभी नहीं हुआ है और शायद कभी भी न हो।

दरअसल, दिल न मिलने की कई वजहों में एक वजह यह भी है कि अतीत के कटु अनुभवों के कारण भारत को चीन पर भरोसा करने का कोई आधार भी नहीं दिखाई देता। मगर हैरानी की बात यह है कि चीन की कथनी और करनी के फर्क को समझने के बावजूद भारत ने अतीत के हादसों से कोई

सबक नहीं लिया। लद्दाख से लगी भारतीय सीमा में चीन के सैनिक तंबूओं का गाड़ना इसी का नतीजा है। चीन पर अविश्वास करने का एक और कारण यह भी है कि वह मौका देखते ही भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने से भी संकोच नहीं करता और ऐसा दबाव बनाए रखकर वह भारत की घेराबंदी के काम में भी लगा हुआ है। चीन की यह घेराबंदी भारत के लिए न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी बहुत खतरनाक है। इस तरह चीन भारत के घावों पर मरहम लगाने के बजाए उन पर नमक छिड़कने का काम ही कर रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत की अदूरदर्शी विदेश नीति और चीन के साथ रिश्तों को लेकर स्पष्ट नीति के अभाव में भी चीन को अपनी भारत विरोधी योजनाओं को आकार देने में मदद मिल रही है। इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार डॉ. वेद प्रताप वैदिक का कहना है- 'चीन की तिकड़मों के आगे हमारी सरकार निढ़ाल दिखाई देती है।' भारत सरकार के निढ़ाल होने का ही परिणाम है कि चीन ने न केवल भारत की चौतरफा घेराबंदी कर ली है बल्कि समुद्री रास्तों से भी भारत की घेराबंदी की पूरी तैयारी उसने कर ली है।

चीन सीमा पार के पड़ोसी देशों की मदद से भारत की घेराबंदी करने की जिस योजना पर काम कर रहा है उनमें दो सामरिक कॉरिडोर बनाने की योजना भी शामिल है। इनमें एक ट्रांस काराकोरम कारिडोर है जो पश्चिम चीन से लेकर पाकिस्तान की होरमुज खाड़ी के प्रवेश द्वार पर स्थित ग्वादर बंदरगाह तक फैला है। पाक की सीमा पर यह बंदरगाह भी चीन ने ही बनवाया है। इस समुद्री मार्ग से कहने को तो 40 फीसदी तेल की आपूर्ति होती है पर इसका सामरिक उद्देश्य भारत की नौ सैनिक गतिविधियों पर नजर रखना है। इसी तरह एक दूसरा कारिडोर चीन ने यूनान प्रांत से लेकर म्यांमार तक बनाया है। इस कारिडोर की मदद से चीन वर्मा के जल और रेल मार्ग का उपयोग कर आसानी से बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। म्यांमार में चीन के दो बंदरगाह क्याउक्यापू और थिलाना में बने हैं। इसके साथ ही चीन ने पूर्वी-पश्चिमी धुरी पर एक तीसरा कारिडोर भी अपने नियंत्रण में ले रखा है। इस सीमा क्षेत्र में गोरमु से ल्हासा तक बना चीन का नया रेल मार्ग भारत की मुश्किलें और बढ़ाएगा।

चीन अपने कब्जे वाले तिब्बत की रेल लाइन को भारतीय सीमा पर चुम्बा घाटी तक पहुंचाने की फिराक में भी है। इससे चीन को यह फायदा होगा कि इस घाटी से मिलने वाली सिक्किम, भूटान, अरूणाचल और म्यांमार की सीमाओं से लगे जंक्शनों पर उसकी पहुंच और आसान हो जाएगी। इसके साथ ही नेपाल की राजधानी काठमांडू को भी रेल मार्ग के जरिए तिब्बत से जोड़ने की मुहिम पर भी उसका काम जारी है। भारत को घेरने की उसकी योजनाएं केवल बंदरगाहों और रेल मार्गों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसने तो भारतीय सीमा क्षेत्र के समानान्तर हवाई अड्डों का निर्माण कार्य भी

साथ-साथ जारी रखा है। भारत की घेराबंदी को लेकर चीन एक चौथे कारिडोर पर भी काम कर रहा है। हिन्द महासागर की समुद्री सीमा पर प्रस्तावित यह कारिडोर 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' यानी मणियों की माला भारत के लिए समुद्री मार्ग से होने वाले चीनी अतिक्रमण के खतरे को बढ़ा देगा।

15 या 16 अप्रैल, 2013 को सीमावर्ती इलाकों से मिली खबरों के मुताबिक यह जानकारी मिली कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी के दक्षिणी हिस्से में देवसांग क्षेत्र के अंदर भारतीय सीमा के 19 कि. मी. इलाके में चीनी सेना की एक 30 सदस्यीय टुकड़ी ने अपने तंबू गाड़ दिए थे। कहा तो यह भी गया कि चीन की सैन्य टुकड़ी ने भारतीय सीमा में 30 कि.मी. अंदर आकर अपने तंबू गाड़ दिए हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि चीन के सैनिकों की संख्या कितनी थी और उन्होंने कितने अंदर तक आकर अपने शिविर स्थापित कर लिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब चीन के सैनिक भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर रहे थे, तब हमारी सेना या अर्द्धसैनिक बल के जवान कहां थे और उन्होंने कोई प्रतिरोध क्यों नहीं किया? सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या हमारी सैनिक या अर्द्धसैनिक बल की टुकड़ी सैन्य बल और ताकत में चीनी सैन्य बल से कमजोर थी या फिर हमारी सैन्य टुकड़ी को उसके राजनीतिक आकाओं से प्रतिरोध के आदेश नहीं मिले थे। ये बात अलग है कि भारतीय सेना ने भी चीन की देखा-देखी अपने कुछ तंबू भी वहां गाड़ दिए पर इसके अलावा प्रतिरोध का कोई दूसरा रूप वहां दिखाई नहीं दिया। बाद में चीन के सैनिक चुपचाप वहां से चले गए। परंतु 21 दिन चले इस घटनाक्रम में भारतीय विदेश नीति का यह हाल रहा कि चीनी सेना को भारत के अपने क्षेत्र से हटाने के लिए चुमार में भारतीय सेना के बनाए बंकरों को हटाने के बाद सहमति बनी। पर इससे पहले भारत की ओर से किए गए राजनयिक प्रयासों के जवाब में चीन ने बातचीत के जरिए मसला हल करने की बात तो जरूर की थी पर साथ ही साथ पेइचिंग से यह संदेश भी अपने सैनिकों तक पहुंचा दिया कि वह किसी भी हालत में अपने स्थान से नहीं हटे। इस तरह चीन हमेशा ही अपनी उस नीति को आगे कर देता है जिसमें पहले जबरन दूसरे की धरती पर कब्जा करने की पहल की जाती है और बाद में बातचीत के रास्ते समस्या के हल का प्रस्ताव रखा जाता है। दौलत बेग ओल्डी के एक हिस्से में जबरन अपने सैनिक तंबू गाड़ देने के मामले में भी चीन ने वही रास्ता अपनाया।

दरअसल चीन भारत तक यह संदेश साफ तौर पर पहुंचाना चाहता है कि वह भारत के साथ सीमा विवाद संबंधी मामलों में भारत की परंपरागत सीमा रेखा को कोई महत्व नहीं देता और मैक-मोहन लाइन संबंधी हल उसे मान्य नहीं है। कहा जा सकता है कि कुछ फेरबदल के साथ चीन भारत के साथ सीमा विवाद को तिब्बत, ताईवान और जी जियांग के साथ उसके सीमा विवाद से किसी भी अर्थ में अलग देख कर नहीं चलता। चीन की नीतिगत संबंधी दृष्टिकोण में एक साफ अंतर इस रूप में देखा जा सकता है। चीन की पुरानी सीमा नीति भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दों को ताईवान,

तिब्बत और जी जियांग जैसे मूल क्षेत्रीय सुरक्षा हितों से अलग करके देखती थी परंतु वास्तव में वैसी स्थिति नहीं है। चीन ने अपने को महानायक रूप में ग्रेटर चाइना के हितों की सुरक्षा करने के आदेश सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को दे दिए हैं। पेइचिंग से प्राप्त इन्हीं आदेशों के अनुपालन में चीनी सैनिक सीमा विवाद के मामलों में वही आचरण भारतीय सीमा में भी कर रहे हैं जो अब तक चीन, तिब्बत, ताईवान और जीजियांग के साथ करता आया है।

हैरानी की बात यह है कि यह सब तब हो रहा था जब इस विवाद से कुछ ही महीने पहले जनवरी 2013 के मध्य में चीन के प्रधानमंत्री जी जियांग ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिख कर आश्वस्त किया था कि चीन भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सर्वाधिक प्राथमिकता देगा। पर इस आश्वासन के कुछ माह बाद ही मैकमोहन लाइन और भारत-चीन के बीच परंपरागत सीमा रेखा को स्वीकार न करने के संकेत देकर चीन ने एक बार फिर अपने पूर्व प्रधानमंत्री चाउ-एन-लाई के रास्ते पर चलने की हामी भर दी। गौरतलब है कि चीन के इन्हीं प्रधानमंत्री ने पहले हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा दिया था फिर भारत की पीठ में छुरा भोंका था। अतीत के उस धोखे से सबक लेकर भारत को चीन के मौजूदा नेतृत्व से न केवल सतर्क रहने की जरूरत है बल्कि मौका मिलने पर चीन से बदला लेने के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर समय रहते एहतियात नहीं बरते गए तो भारत-चीन सीमा के मध्य में तैनात चीन के 25 लाख सैनिक भारतीय भू-भाग में कब्जा करने का अपना कुचक्र जारी रखेंगे।

भारत चीन के बीच सीमा विवाद का यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अप्रैल 2013 के तीसरे सप्ताह लद्दाख क्षेत्र में की गई चीन की सैनिक कार्रवाई से कुछ माह पहले तक के दो वर्षों (2010-12) के दौरान चीन ने भारत की नियंत्रण रेखा और मैकमोहन लाईन का 600 से अधिक बार अतिक्रमण किया जिससे भारत के ऊपर 750 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारत के प्रधानमंत्री का चीन के ताजा विवाद को एक स्थानीय मसला कहकर हल्के में लेना और विदेश मंत्री का यह कहना कि इसे कूटनीतिक मरहम से सुलझाया जा सकता है, किसी के भी गले नहीं उतर रहा है।

सच्चाई तो यह है कि चीन भारत समेत किसी भी देश के साथ अपने सीमा विवाद हल करना ही नहीं चाहता चाहे वह ताईवान, तिब्बत या फिर कोई दूसरा देश ही क्यों न हो। तिब्बत और ताईवान पर तो उसने स्थाई कब्जा कर लिया है पर भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए वह कभी अरूणाचल तो कभी कश्मीर तो कभी कोई और मुद्दा उठाकर भारत के साथ सीमा विवाद को हमेशा

ही जीवंत रखना चाहता है ताकि किसी न किसी बहाने भारत के साथ सीमा विवाद के ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मंचों की सुर्खियों में बने रहे।

अजीब बात यह है कि एक ओर चीन भारत की सीमा पर अपने तंबू गाड़ कर समस्या का आपसी बातचीत से हल निकालने की बात करता है तो दूसरी ओर भारत को आंख दिखा कर सीमा क्षेत्र में आधारभूत ढ़ांचा को खड़ा करने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों को बंद करने की धमकी देता रहता है।

भारत और चीन के बीच चल रहे मौजूदा शीत युद्ध को लेकर जाने-माने सामरिक विशेषज्ञ भरत वर्मा का कहना है कि चीन ने भारत को लेकर जो डिजाइन तैयार किया है वह दो स्तरीय है। एक स्तर पर भारत और चीन दोनों देशों द्वारा हथियाई गई जमीनों की वापसी का मसला है और दूसरे स्तर पर चीन को यह भरोसा है कि वह देर-सबेर भारत के कब्जे वाली अपनी जमीन तो हर हालत में वापस ले ही लेगा। पर अपने कब्जे वाली भारत की जमीन को वापस करने के बजाए वह भारत के दूसरे स्थानों पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए है। श्री वर्मा ने पिछले दिनों दिल्ली से प्रकाशित एक पत्रिका में चीन की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी टिप्पणी की थी। इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने भारत को कई कोणों से अस्थिर बनाने की योजनाएं भी बनाई हैं। अगर वह अपने इन नापाक मंसूबों को हासिल करने में कामयाब हो गया तो भारत के पास चीन की गुलामी के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अपने इन्हीं नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए चीन पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, मालदीव और सेसेल्स तक कई देशों का उपयोग करने की हर संभव कोशिश कर रहा है।

हैरानी तो तब होती है कि यह सब जानने समझने के बाद भी भारत सरकार चीन द्वारा भारत की लद्दाख सीमा में किए गए ताजा अतिक्रमण को स्थानीय मसला कह कर टाल देती है। तकलीफदेह बात यह भी है कि हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इस घटना को चेहरे पर निकल आए मुंहासों की संज्ञा देते हुए मरहम लगा कर इन मुंहासे को दबा देने की बात करते हैं। पर मामला इतना आसान नहीं है। सही बात तो यह है कि चीन इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि आने वाले वर्षों में भारत एक वैश्विक ताकत के रूप में उभर सकता है जो चीन कभी नहीं होने देगा। इसीलिए चीन हर संभव कोशिश कर भारत को सामरिक, आर्थिक, और राजनीतिक हर दृष्टि से अस्थिर कर देना चाहता है चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। चीन की इन कोशिशों से अगर भारत अस्थिर हो जाता है तो फिर उसके विश्व शक्ति के रूप में उभरने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। उनके शब्दों में “अनेक

अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट यह कहती हैं कि अगले 20-30 साल में भारत आर्थिक रूप से तीसरी मुख्य वैश्विक शक्ति बन सकता है। चीन की कोशिश है कि ऐसी स्थिति आने से पहले ही भारत को अस्थिर कर दिया जाए।" सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि चीन भारत उदय की हर कोशिश को बर्बाद कर देना चाहता है और उसकी भूमंडलीय प्रतिष्ठा को पंचर कर देना चाहता है। इसके लिए सीमा विवाद को जिन्दा रखने और पड़ोसी देशों की ओर से भारत पर लगातार दबाव बनाए रखने की कोशिशें वह हमेशा ही जारी रखेगा।

चीन की घृणित और कुत्सित विस्तारवादी नीति के कई कारणों में एक कारण यह भी है कि चीन अपने अंदरूनी हालातों पर से ध्यान बंटाने की गरज से भी इस अभियान में लगा हुआ है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि चीन तिब्बत और जीजियांग क्षेत्र में फैले आंतरिक असंतोष और हिंसा के मामलों से अपनी जनता का ध्यान बंटाने के लिए सीमा विस्तार के विवाद को आगे बढ़ाता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अकेले चीन के जीजियांग क्षेत्र में फैले असंतोष और हिंसा के मामलों में 2009 से अबतक लगभग 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं, दूसरी ओर चीन के मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो अपने लिए एक अलग स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग कर रहा है। इसके अलावा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे इस देश में मजदूर आंदोलन, असमान वृद्धि दर, बढ़ती आबादी जैसे मुद्दों ने भी चीन की सरकार के सामने गंभीर समस्या पैदा कर दी है। इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए उसके पास सीमा विवाद और साम्राज्य के विस्तार का रास्ता ही शेष बचता है। चीन के भारत, जापान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई और फिलीपीन्स जैसे देशों के साथ कड़वे संबंध इस हकीकत को बयान करते हैं।

चीन के लिए आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भारत की घेराबंदी का ही है क्योंकि तुलनात्मक रूप में वह दक्षिण एशिया के सभी देशों में भारत को ही एकमात्र ऐसे देश के रूप में देखता है जो देर सबेर विश्व शक्ति बनने की क्षमता रखता है और इस देश की अपनी एक लोकतांत्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हैसियत भी है। चीन भारत की इसी बहुआयामी हैसियत को चुनौती देने की फिराक में रहता है। चुनौतियां देने के इसी क्रम में चीन दक्षिण एशिया के भारत के पड़ोसी देशों के भूभाग में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर भारत की घेराबंदी करने से बाज नहीं आता। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि चीन ने भारत की घेराबंदी के लिए जो रणनीति अख्तियार की है वह कहीं न कहीं अमेरिका द्वारा की गई सोवियत संघ की सामरिक घेराबंदी की याद दिला देती है। गौरतलब है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ के आसपास के कई देशों के साथ ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर इन देशों को सोवियत संघ के खिलाफ चलाई गई मुहिम में अपने पक्ष में कर लिया था। जिसकी परिणति बाद में सोवियत संघ के विघटन के रूप

में सामने आई थी। कुछ ऐसी ही हालत आज चीन की भी है जो भारत के पड़ोसी देशों से मिलकर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल है। इस क्रम में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान तथा मालदीव समेत कई देशों को न केवल आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन देशों का राजनयिक समर्थन कर इन देशों के भूभाग का इस्तेमाल अपने सामरिक कार्यों के लिए कर रहा है। इनमें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर हवाई अड्डे बनाना भी एक काम है। हवाई अड्डों के साथ ही चीन ने भारत के पड़ोसी देशों में बंदरगाह भी बनाए हैं जो चीन के लिए लिसनिंग पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के केंद्रों के रूप में काम कर रहे हैं। इन बंदरगाहों तक अपनी सीधी पहुंच बनाकर चीन हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। भारत के पड़ोसी देशों के अलावा चीन की नजर सेसेल्स, मॉरीसस और मेडागास्कर जैसे देशों पर भी है। इन देशों के साथ भी चीन अपने नौ सैनिक एवं व्यापारिक रिश्ते बनाने में दिलचस्पी ले रहा है।

पाकिस्तान

भारत-चीन युद्ध के बाद से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत-विरोधी धुरी बनाने की कोशिश करता रहा है। चीन की इस रणनीति पर वेदप्रताप वैदिक कहते हैं 'चीन ने अपने मोहरे पाकिस्तान को दराज़ से निकालकर दुबारा मेज़ पर रख लिया है। उसे अब वह दक्षिण एशिया की शतरंज पर जमकर चला रहा है।' लगभग एक दशक पहले चीन ने यह कहना शुरू किया था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है और वे उसे बातचीत से हल करें लेकिन, पिछले कुछ वर्षों से उसने कश्मीर के मसले को नया रंग दे दिया है। भारत के कश्मीर से चीन की यात्रा करने वाले नागरिकों को वह सामान्य वीजा नहीं देता है। वह एक अलग कागज पर ठप्पा लगाकर देता है क्योंकि वह जम्मू-कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानता। लेकिन यदि वह संपूर्ण जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को विवादास्पद मानता है, तो पाकिस्तानी कब्जे के कश्मीरियों को बाकायदा वीजा क्यों देता है? इसका अर्थ स्पष्ट है। चीन जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है।

उपरोक्त तथ्य इस ओर भी इशारा करते हैं कि पाकिस्तान को उकसाकर चीन न सिर्फ भारत के लिए स्थायी सिरदर्द का इंतजाम कर देगा बल्कि वह दक्षिण, मध्य और पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ भी मजबूत बनाएगा। चीन ने पाकिस्तान की भारत-विरोधी हर मुहिम में मदद की, उसे परमाणु बम और उसकी तकनीक भेंट की, प्रचुर आर्थिक सहायता और कूटनीतिक मदद भी दी। चीन ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि शीतयुद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका का मोहरा रहा था।

चीन ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत के ग्वादर में जो बंदरगाह बनाया है वह भारत के लिए बहुत खतरनाक है। इससे चीन को जहां तेल व्यापार के लिए एक बेहतर मार्ग मिलेगा वहीं यह बंदरगाह उसके लिए लिसनिंग पोस्ट का भी काम करेगा जहां से वह फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों और अरब की खाड़ी में भारत की गतिविधियों तथा भारत अमेरिकी नौसैनिक सहयोग पर नजर रख सकेगा। पता यह भी चला है कि चीन ने वहां पर खुफिया उपकरण लगा दिए हैं जिनके जरिए वह होमरूज की खाड़ी और अरब सागर के समुद्री परिवहन पर निगरानी रख रहा है। इसके अलावा चीन ने पाक के पासनी और ओरमारा में भी अड्डे बनाए हैं।

बांग्लादेश

बांग्लादेश में भी चीन आर्थिक-सैनिक मदद और बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग के बदले सामरिक सुविधाएं लेने का खेल बखूबी खेल रहा है। चटगांव में बंदरगाह के अलावा उसने दूसरे पद्मा ब्रिज को बनाने में वहां की सरकार की मदद की है। वह इस कोशिश में भी लगा हुआ है कि बांग्लादेश म्यांमार के रास्ते चीन तक रेलमार्ग और थलमार्ग बनाने पर सहमत हो जाए। बांग्लादेश के साथ चीन ने सुरक्षा संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं हालांकि उसके प्रारूप को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

श्रीलंका

श्रीलंका के दक्षिणी किनारे पर हम्बनटोटा में चीन बंदरगाह बना रहा है। वहां से मात्र दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह दुनिया के व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है। हिंद महासागर की निगरानी करके चीन को सउदी तेल की सप्लाई को सुनिश्चित करनेवाली चीनी नौसेना एक अरब डालर की भारी लागत से बने इस बंदरगाह को इंधन भरने और डाकिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करती है। श्रीलंका ने चीन को मन्नार बेसिन में पैट्रोल की खोज के लिए एक ब्लाक आबंटित किया। इस आबंटन का लाभ चीन को यह हुआ कि भारत के दक्षिणी सिरे से कुछ मील दूर चीन की मौजूदगी हो गई। आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र में भारत का एकाधिकार खत्म हो गया है और उसे चीनी कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बदले में चीन ने श्रीलंका को लिट्टे से कुचलने के लिए हथियार और विश्व मंच पर राजनयिक समर्थन प्रदान किया। पिछले कुछ वर्षों में चीन इस छोटे से देश के लिए सबसे बड़ा दानदाता बन गया है।

म्यांमार

चीन का पहला सुरक्षा कोरिडोर पाकिस्तान के साथ बना है तो दूसरा म्यांमार में। उसने म्यांमार के सीटवे में बंदरगाह बनाया है जिसके जरिए वह हिंद महासागर तक पहुंचने का इरादा रखता है। इस सुविधा के बदले में चीन ने म्यांमार को हथियार, लड़ाकू विमान और युद्धपोत मुहैया कराए और उसके थल और वायु सैनिकों को प्रशिक्षित किया। दोनों देशों ने मार्च में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिसका मसौदा था दोनों देशों के बीच तेल व गैस की पाइप लाइन बिछाना ताकि चीन को तेल के जहाज ले जाने के लिए मलक्का जलडमरूमध्य का लंबा रास्ता तय न करना पड़े। म्यांमार की सैनिक सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए चीन से हथियार लेती है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में म्यांमार के बचाव में चीन अपनी स्थायी सदस्यता और वीटो के अधिकार का उपयोग हमेशा करता है।

नेपाल-भूटान

भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले नेपाल और भूटान को चीन लगातार अपने साथ लाने की कोशिश में लगा रहता है। नेपाल में माओवादियों के सत्ता में आने के बाद से चीन के लिए हालात अनुकूल हो गए हैं। चीन भी माओवादियों को सत्ता में बनाए रखने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले चीन ने माओवादियों के लिए नेपाली सांसदों को खरीदने की कोशिश भी की थी। बाद में इस साजिश का खुलासा हुआ था। चीन नेपाल के साथ एक ऐसी मैत्री करना चाहता है जो 1950 की भारत-नेपाल संधि को बेअसर कर दे।

चीन ने भूटान के सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपनी गतिविधियां तेज की हैं जो भारत के "चिकन्स नेक" कहलाए जाने वाले क्षेत्र के निकट हैं। यह सिलिगुड़ी का वह संकरा इलाका है जो मुख्य भारत को उत्तर पूर्व के साथ जोड़ता है।

मालदीव

चीन ने मालदीव के मराओ में भी अपना नौसैनिक अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा है। दो साल की लंबी बातचीत के बाद 2001 में चीन के प्रधानमंत्री की माले यात्रा के दौरान इस बारे में समझौता हो गया था।

चीन की मान्यता रही है कि वह इन देशों में अपने अड्डे केवल इसलिए बना रहा है ताकि अपनी सरपट

चाल से दौड़ती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित कर सके मगर सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन सामरिक अड्डों से चीन भारत को घेरना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगा सके। पिछले कुछ दशकों में चीन के नौसैनिक रणनीतिकारों का ध्यान हिंद महासागर और समुद्री परिवहन के मार्गो की ओर गया है। चीन अपनी नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में पहले से ज्यादा सक्रिय करना चाहता है। उसकी इस नई पहल पर दीपांजय राय चौधरी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि चीन ने दुनिया को यह संकेत दे दिया है कि वह अपनी प्राकृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक समुद्री सीमाओं से परे जाकर भूमिका निभाने की महत्त्वाकांक्षा रखता है। निकट भविष्य में भारत के समुद्री हितों को चीन की किसी भी चुनौती का सामना उसके आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप के साथ ही सैनिक स्वरूप और आर्थिक तंत्र के साथ भी करना होगा चीन के सैनिक अड्डों की शृंखला का विकास उसकी वैश्विक शक्ति प्रदर्शनी का ही एक अंग है।

म्यांमार चीन पर बढ़ती निर्भरता से चिंतित है और वह भारत से भी सैनिक सप्लाई की गुहार कर रहा है। कंबोडिया में चीन दक्षिणी चीन से समुद्र तक रेललाईन बिछाने में मदद कर रहा है। थाईलैंड में क्राइस्थुमस में 20 अरब डालर की लागत से नहर निर्माण को वित्तीय सहायता दे रहा है।

चीन केवल हथियारों और बंदरगाहों की महत्ता तक अपनी रणनीति सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि वह मध्यपूर्व, दक्षिण और पूर्वी एशिया के ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर एनर्जी डिप्लोमैसी के जरिए भारत को कमजोर करना चाहता है। ...चीन भारत को केवल एक मोर्चे पर नहीं बल्कि आर्थिक और सामरिक दोनों ही मोर्चों पर घेरने की कोशिश में है। चीन पाकिस्तान आधारित आतंकवाद को परोक्ष समर्थन करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर व लश्कर-ए-तैयबा के आजम चीमा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जब भारत की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था, तो चीन ने उसका विरोध किया था।

भारत के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमा पर चीन एक तरफ सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है और ऐसा बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है जिससे सेनाओं को कम से कम समय में भारतीय सीमा पर लाया जा सके। दूसरी तरफ अपने सीमावर्ती इलाकों में और पाक शासित गिलगिट, बाल्टिस्तान में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जाल बिछा रहा है। पिछले वर्ष *न्यूयार्क टाईम्स* में छपी रपट में कहा गया है कि हाल ही में गिलगिट बाल्टिस्तान में दो महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। एक तरफ देश में पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है तो दूसरी तरफ इस क्षेत्र में 7000 से 10000 तक चीनी सैनिकों ने घुसपैठ भी की है।

चीन सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र को अपने शिकंजे में लेना चाहता है ताकि पाकिस्तान के रास्ते खाड़ी देशों तक पहुंचने के लिए निर्बाध सड़क और रेलमार्ग बना सके। इस लिंक से चीन अपने पूर्वी हिस्सों में कार्गो और तेल टैंकर पाकिस्तान के बलोचिस्तान में उसके द्वारा बनाए जा रहे नौसैनिक अड्डों तक पहुंचा सके। जहां से खाड़ी देशों के पूर्वी किनारे मात्र 48 घंटों की दूरी पर है। एक अंदाज यह भी है कि चीन वहां पर 17 परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई वार्षिक रपट में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि चीन ने निरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए नए लंबी दूरी तक मार करने वाले सीएसएस-5 मिसाइल भारत की सीमा के पास तैनात किए हैं और इस इलाके में बहुत कम समय में हवाई दल लाने के लिए कंटिन्जेंसी प्लान बनाया है। रपट के मुताबिक उपग्रह द्वारा प्राप्त बैलिस्टिक मिसाइलों की तस्वीरों से स्पष्ट है कि मध्य चीन के क्वींगई प्रांत में एटमी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 60 लांचिंग पैड बनाए गए हैं जो आसानी से उत्तर भारत को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा चीन के नए टीएफ 13ए मिसाइल ऐसे हैं जो 11,200 किमी दूरी तक मार कर सकते हैं और पनडुब्बी से छोड़े जानेवाले मिसाइल 7200 किमी तक मार कर सकते हैं जिनसे अमेरिका चिंतित है।

भारत के उत्तर में चीन की घेराबंदी कितनी विकट है इसका एक अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल तिब्बत में 200,000 की सेना तैनात कर चुका है। वह वहां मिसाइल लांचिंग पैड, हवाई अड्डे और राजमार्ग निर्माण पर अरबों डालर खर्च कर रहा है ताकि भारत की सीमा पर अतिरिक्त सेनाएं पहुंचा सके।

वैसे भारत की चीन समर्थक पार्टियां भारत पर ही चीन की घेराबंदी करने का आरोप लगा रहीं हैं। माकपा के नीलोत्पल बसु ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चीन की 90 फीसदी हाईड्रो कार्बन सप्लाई मलाका खाड़ी के जरिए होती है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा से पहले भारत के रक्षामंत्री ने जिस रक्षा और सैन्य फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें कई आपत्तिजनक बातें हैं। इसने चीन के मन में कई तरह की आशंकाओं को जन्म दिया है। अगर भारत इस क्षेत्र में अमेरिका के समग्र सैनिक गेमप्लान का हिस्सा बन जाता है - जिसका मकसद मलाका खाड़ी पर नियंत्रण रखना भी है तो ऐसे में चीन से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा। माकपा के महासचिव प्रकाश करात ने भी चीन का पक्ष लेते हुए कहा है कि हमें अमेरिका के साथ ऐसा कोई करार स्वीकार नहीं होगा जिसका मकसद चीन को घेरना या उसके प्रभाव पर अंकुश लगाना हो। चीन के प्रति ऐसी हमदर्दी दिखाकर भारत के वामपंथी आखिर कहना क्या चाहते हैं?

यदि भारत चीन की नौसेना के प्रभाव को सीमित रखना चाहता है तो उसे सामरिक महत्त्व के स्थानों पर अपनी नौशक्ति का दबाव बढ़ाना चाहिए। यदि भारत महत्त्वपूर्ण देशों के साथ सामरिक भागीदारी द्वारा हिंद महासागर के विभिन्न प्रवेश द्वारों की रक्षा नहीं करेगा तो उसे चीनी नौसेना का बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सामना करना पड़ेगा।

अध्याय-तीन

भारत-चीन सीमा विवाद की पृष्ठभूमि

भारत चीन का मौजूदा सीमा विवाद चीन के पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की 2010 की भारत यात्रा के बाद ही गहराता गया था। चीनी प्रधानमंत्री की उक्त यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पारस्परिक महत्व के अनेक मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद की जा रही थी। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। समस्या सुलझने के बजाए उलझ गई और दोनों देश तकरीबन 3,500 कि.मी. की सीमा रेखा को लेकर कोई सार्थक बातचीत नहीं कर सके। चीन के सरकारी पत्र ने यहां तक कह दिया था कि भारत और चीन की सीमा महज 2,000 किमी. तक सिमटी हुई है। *पीपुल्स डेली* समाचार पत्र ने भारतीय प्रमाण को गलत और बेबुनियाद बताया।[1] यह सब कुछ चीन के सरकारी पत्र में उसी समय प्रकाशित किया गया जब चीन के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर थे। चीन में तत्कालीन भारतीय राजदूत श्री एस. जयशंकर ने चीन की दलील को एक खतरे का संकेत माना है।[2] सितंबर 2010 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी यह कहा था कि चीन जानबूझकर भारत के उन संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है जो भारतीय सुरक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।[3]

चीन की सोच में सीमा विवाद को लेकर बुनियादी बदलाव देखा जा सकता है। चीन ने बड़ी ही कुटिलता के साथ सीमा विवाद को अपने सामरिक विस्तार के मोहरे की तरह प्रयोग किया है। सीमा विवाद का हल ढूंढने का प्रयास दोनो देशों के बीच 1981 से ही किया जा रहा है। अब तक सीमा विवाद को लेकर 14 सत्रों की वार्ता दोनो देशों के बीच हो चुकी है। लेकिन बात सुलझने के बजाय और उलझती ही जा रही है। क्योंकि चीन जान बूझकर ऐसा कर रहा है। चीन जम्मू-कश्मीर को विवादास्पद क्षेत्र कहता है, तो उसका कारण सिर्फ पाकिस्तान को खुश करना नहीं है, बल्कि चीन इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाकर भारतीय सुरक्षा को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश में है।[4] उल्लेखनीय है कि अक्साईचीन में सड़क निर्माण के कारण ही चीन ने सीमा विवाद को 1960-62 के बीच विस्फोटक बनाया था। इसी मार्ग से लौकनोर में परमाणविक अस्त्रों के परीक्षण स्थल तक

उसकी पहुंच बनती है। दरअसल यहीं से पाक-अधिकृत कश्मीर के रास्ते चीन ग्वादर के बंदरगाह तक पहुंच सकता है।

चीन भारत की सीमाओं के इर्द-गिर्द सामरिक जाल बुनने का काम पिछले कई वर्षों से कर रहा है। हिमालय की तराई में बसे देशों के बीच सड़क और रेल संपर्कों का निर्माण चीन की चाल है। चीन के काश्गर और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को जोड़ने वाले काराकोरम हाइवे की लंबाई 1300 किमी. है। इस राजमार्ग को 'फ्रेंडशिप हाईवे' का नाम दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से चीन द्वारा इस सड़क की चौड़ाई 10 मी. से 30 मी. तक बढ़ाई जा चुकी है। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है कि युद्ध या संघर्ष की स्थिति में उसकी सेना और सैन्य सामान को एक जगह से दूसरे जगह द्रुत गति से पहुंचाया जा सके।

हाल के कुछ वर्षों में चीन के सामरिक विस्तार को समझते हुए आसानी से कहा जा सकता है कि भारत ही उसका प्रमुख लक्ष्य है। दरअसल मौजूदा हालात 1960-62 से भी बदतर है।[5] सितम्बर 1962 को चीन की सेना ने 'यागलारिज' पर आक्रमण कर दिया था और भारत की सेना पीछे हट गई थी। पुनः पूर्वी सीमा के भीतर तक पी.एल.ए. की सेना जा घुसी थी। पश्चिमी सीमा पर चीन ने तकरीबन 13 भारतीय सैनिक ठिकानो पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 24 घंटे के भीतर चीन की सेना उन जगहों को छोड़कर अपने बैरक में वापस लौट गई थी[6]। मौजूदा हालात और चीन की नीयत दोनों ही समीकरण 1962 से भी खतरनाक है। इस बार चीन ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर नए सिरे से विवाद को जन्म देकर चीन ने भारत की अखंडता पर प्रश्न उठाया है। कश्मीर का भौगोलिक ढांचा तीन भागों में बंटा हुआ है। 45 प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है। 35 प्रतिशत चीन के पास शेष 20 प्रतिशत पाकिस्तान ने हड़प रखा है।[7] चीन सुनियोजित ढंग से पाक-अधिकृत कश्मीर में अपना सैनिक विस्तार कर भारत की सुरक्षा को और कमजोर करना चाहता है।

चीन भारत को अपने गंभीर प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। इसलिए वह हर कीमत पर भारत को कमजोर करने की कोशिश में है और इसके लिए हर प्रकार की जोर आजमाईश ा कर रहा है। चीन के सरकारी पत्र *'पीपुल्स डेली'* में यह कहा गया कि "भारत किसी भी तरह चीन का मुकाबला नहीं कर सकता[8]।" एक दूसरे पत्र में चाइनीज विश्लेषक दाई वींग ने यह माना कि "संभवतः भारत और चीन के बीच भले ही युद्ध न हो लेकिन शीत युद्ध की गर्मी युद्ध का माहौल तैयार कर सकती है। प्रो. अमिताभ मट्टू के अनुसार चीन हर तरह से इस बात की ताकीद कर रहा है कि एि शया में एक मात्र शक्ति चीन ही है।[9] इसलिए चीन अपनी सामरिक शक्तियों का न केवल प्रसार कर रहा है बल्कि

उन शक्तियों का पाइलट परीक्षण भी कर रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञ मोहन मलिक के अनुसार चीन भारत को एक शक्ति के रूप में उभरने नहीं देना चाहता। चीन ने 2005 के पहले ऐसा कभी नहीं कहा कि अरूणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है या 1962 का "अधूरा काम"। चीन की नीति में तीखापन 2005 में आया। मलिक यह मानते हैं कि चीन यह सब कुछ जानबूझ कर कर रहा है।[10] उल्लेखनीय है कि चीन के भीतर पी.एल.ए. अर्थात चीन की सेना महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बन चुकी है। रिसर्च और एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख बी रमन का मानना है कि पी.एल.ए. का प्रशिक्षण पूरी तरह से भारत-विरोधी है।[11]

दूसरी तरफ भारत-चीन नीतियों के नीति निर्धारक आज भी भ्रम में जी रहे हैं। 1962 में मिली शिकस्त के बावजूद यह माना जा रहा है कि भारत 1962 जैसी स्थिति पैदा नहीं होने देगा। लेकिन जिस तरह की चूक की वजह से भारत ने 1962 के युद्ध में मात खाई थी संभवतः उसी तरह की भूल आज भी की जा रही है। 2010 में पेंटागन की रिपोर्ट में साफ तौर पर माना गया है कि चीन की युद्ध नीति और सैनिक सिद्धांत पूरी तरह से रहस्यपूर्ण है। पूरी दुनिया को विशेषकर भारत को नहीं मालूम कि चीन का अगला कदम क्या होगा।

दरअसल, 1962 के युद्ध के पहले भारत इस भ्रम में था कि चीन कभी भी भारत से युद्ध नहीं करेगा। इसी क्षद्म आकलन के कारण भारत के पास न तो कोई सार्थक चीन नीति थी और न ही दक्षिण एशियाई नीति। आज जिस तरीके से चीन 1962 के युद्ध के पांच दशक बाद पूरे दक्षिण एशिया में फैलकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है, वह चीन के विस्तारवाद और भारत की दृष्टिहीनता की वजह से ही हो पाया है। ब्रिटिश साम्राज्य की सोच दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर के संदर्भ में एक समग्र रूप में थी। ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत तक को एक बफर लाईन मानती थी, जिसकी लकीरें उत्तरी बर्मा तक फैली हुई थी। समुद्री मुहानों पर यह लाईन लाल सागर से मल्लका स्ट्रीट तक फैली हुई थी।[12] लेखक जान गार्वर ने यह माना है कि भारत को विरासत में एक ऐसा सामरिक ढांचा मिला था, जिसे भारतीय राजनीतिज्ञों ने आदर्शवाद की मोह में तोड़ दिया। कई रक्षा विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अगर नेहरू में सामरिक सूझ-बूझ होती तो भारत न केवल 1962 का युद्ध जीत जाता बल्कि 1962 के बाद बनी भारत के गले में सुरक्षा की हड्डी यानि कश्मीर समस्या भी नहीं होती और तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश होता। भारत की सुरक्षा उत्तरी सीमा से पूरी तरह चाक-चौबंद होती। ब्रह्मपुत्र की धाराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होता। तिब्बत आण्विक प्रक्षेपास्त्रों का अड्डा नहीं बनता। भारत में नक्सलवाद की लपटें नहीं उठती जो आज हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अहम प्रश्न बन गया है।

संदर्भ

1. के. सुब्रमन्यम, 'चीन से सावधानी की जरूरत' टाइम्स ऑफ इंडिया 23 सितंबर
2. ....'चीन से उत्पन्न संकट' तहलका रिपोर्ट, 1 नवंबर 2010
3. नेहा कुमार, 'चीन से आण्विक बमों का खतरा, 'इंडिया क्वाटरली, 65, (2009) 37-53
4. नग्वांग ग्यारत सेन, 'ग्रीन तिब्बत' रिपोर्ट, सेंट्रल तिब्बतन प्रशासन, 1996
5. अटल बिहारी बाजपेयी, 'चार दशक संसद में' वॉल्यूम - तीन सिप्रा - 998
6. जॉन अर्कले, 'चीन के आण्विक बम तिब्बत' रिपोर्ट, 1993
7. ब्रहम चिलानी, 'चीन से खतरा' हिंदुस्तान टाइम्स, 15 अक्टूबर 2010
8. जेन्स डिफेंस विकली रिपोर्ट 'चीन की सैन्य शक्ति' मई 2010
9. गुरमीत कनवल, 'चीन की महशक्ति बनना', स्ट्रैटिजिक एनालिसिस, वॉल्यूम 22, 1999
10. मारूफ रजा, 'चीन से दो-दो हाथ' 28 अक्टूबर 2010
11. छाना नोरबू, 'भारत और चीन के बीच तिब्बत' 18 सितंबर, 1999
12. श्रीपरना पाठक, 'चीन, पाकिस्तान और भारत' आसाम ट्रिब्यून, सितंबर 2010

अध्याय-चार

चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए बहुआयामी खतरा

भारत को सामरिक धरातल पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर भी घेरने संबंधी चीन की विस्तारवादी नीति ने भारत के लिए दीर्घकालीन खतरा पैदा कर दिया है। सामरिक स्तर पर चीन ने भारत की जो घेराबंदी कर रखी है उसे तो कूटनीतिक और सामरिक उपायों से जीता भी जा सकता है लेकिन दीवाली की लड़ियों, मोमबत्ती, दियों, होली की पिचकारी, गणेशोत्सव के लिए गणेश की मूर्तियों से लेकर रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुओं, कपड़े, मोबाइल, लाइटर और इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों को सस्ते दामों पर घर-घर तक पहुंचा कर चीन भारत की आर्थिक रीढ़ भी तोड़ देना चाहता है। आज जरूरत इस बात की है कि चीन द्वारा छेड़े गए अघोषित शीतयुद्ध के साथ ही भारत को आर्थिक मंच पर भी उसे कड़ा जवाब देना होगा। पर यह सब करने से पहले भारत को उन तथ्यों की बारीकी से पड़ताल भी करनी होगी जो भारत-चीन संबंधों के बीच गहरी खाई बनने का कारण बने थे। सच्चाई यह है कि इसके पीछे भी चीन की कुटिल चाल ही प्रमुख थी। क्या हैं वो बिन्दु या तथ्य इन्हें जानना सबसे पहले जरूरी है।

- 2003 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी चीन यात्रा के दौरान इस बात पर आम सहमति बनी थी कि कश्मीर का मुद्दा भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर चीन कोई भी भारत-विरोधी टिप्पणी कर दोनों देशों के बीच बन रहे संबंधों में अनावश्यक अवरोध पैदा नहीं करेगा। लेकिन पिछले दिनों पाक-अधिकृत कश्मीर में करीब 10,000 चीनी सैनिकों की उपस्थिति ने पूर्व-निर्धारित शर्तों को तोड़ दिया है और इससे खतरे की नई आशंका पैदा हो गई है।[1]

- जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अलग प्रकार से वीजा देने की शुरूआत इस बात के साफ

संकेत हैं कि चीन कश्मीर को पुनः विषैले नजरिए से आंकने लगा है। इस बात का विरोध भारत की सरकार द्वारा भी किया गया। चीन ने ले. जनरल बी.एस. जमवाल को चीन की यात्रा के लिए वीजा देने तक से इंकार कर दिया।[2]

- 2007 में चीन की सरकार ने 100 से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों को वीजा देने से इंकार कर दिया। कारण यह बताया गया कि उस टीम में अरूणाचल कैडर का भी एक अधिकारी शामिल था। इसी तर्क के आधार पर अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गगोई अपांग को भी चीन की सरकार ने वीजा देने से इंकार कर दिया था। चीन की दलील है कि अरूणाचल प्रदेश चीन का दक्षिणी हिस्सा है।[3] अपने ही देश में आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। चीन अरूणाचल प्रदेश पर भारत का "अवैध कब्जा" मानता है।

- चीन ने दलाईलामा को लेकर काफी बवाल मचाना शुरू कर दिया है। 2010 में दलाई लामा की तवांग यात्रा को अनावश्यक तूल दिया गया। सांस्कृतिक आयोजन में भी दलाई लामा की गतिविधियों को लेकर चीन ने असहमति व्यक्त करने की परंपरा शुरू कर दी। दरअसल यह बदला हुआ मिजाज विश्वासघाती समीकरण का हिस्सा है।

- चीन भारत की सुरक्षा संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय और सेना प्रमुख कार्यालय से संबंधित तथ्यों को साईबर तकनीक द्वारा हैक करने की कोशिश कर रहा है। इस बात की पुष्टि भारत के पूर्व सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन द्वारा की जा चुकी है।[4]

- चीन 60 के दशक से ही भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पैर पसार रहा है। उसका निशाना भारत है। 2007 से चीन की मुहिम तेज हो गई है। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भारत को वैश्विक शक्ति बनने से रोकना चाहता है।[5]

- 2010 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित की गई सुरक्षा रिपोर्ट में भी चीन के आक्रामक रूख की बात कही गई है और अमेरिका द्वारा इस परिवर्तित रूख पर चिंता भी जाहिर की गई है। जापान, दक्षिणी कोरिया और अन्य दक्षिणी पूर्व देशों द्वारा भी चीन की कूटनीति में अड़ियलपन और विस्तारवादी नीतियों के कारण विश्व शांति ओर पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षा का नया खतरा उभरकर सामने आ रहा है।

- वर्ष 2009 में एशियन विकास बैंक द्वारा अरूणाचल प्रदेश हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की राशि को

चीन ने अपने प्रभाव के जरिए रोकने की कोशिश की। यह पहला मौका है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भारत के विरूद्ध उकसाने का काम किया गया।

- चीन द्वारा द्रुतगति से तिब्बत और नेपाल के विभिन्न शहरों को रेल लाईन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ल्हासा से झिज्जे और काठमांडू के बीच रेल लाईन परियोजना का काम शुरू कर दिया गया है। झिज्जे और नयालाम के बीच रेल लाईन बन जाने के बाद काठमांडू की दूरी महज 12 कि.मी. तक सिमट जाएगी। अर्थात् चीन की रेल भारतीय सीमा तक पहुंच जाएगी।[6]

- चीन मनोवैज्ञानिक रूप से भारत को इस तरह से प्रभावित करना चाहता है कि भारत चीन के विकराल रूप से डरकर हर तरह से आत्मसमर्पण कर दे। इस अभ्यास में चीन का मीडिया भी खूब उछल कर ऐसी रिपोर्टें छाप रहा है जिससे भारत में खौफ पैदा हो जाए। भारत को यह चेतावनी भी दी जा रही है कि भारत, चीन विरोधी प्रवृतियों पर न केवल अंकुश डाले बल्कि खुद भी सर्तक रहे।

- 30 अगस्त 2009 को चीन की वायु सेना के हेलिकॉप्टरों ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया। चूमार लेक के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चीन द्वारा खाद्य पदार्थ की सामग्री अनावश्यक रूप से गिराई गई। इस बात की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को दी गई। तकरीबन चीन का अतिक्रमण भारतीय सीमा के 1.5 कि.मी. भीतर तक था। इस अतिक्रमण की गंभीरता चीन की विस्तारवादी चरित्र के कारण बढ़ जाती है।

- चीन हिन्द महासागर में भारतीय पहल का घोर विरोधी रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह विरोध एक षड्यंत्र का हिस्सा दिखाई देने लगा। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति मुख्यतः हिन्द महासागर में अपनी घुसपैठ बनाने से जुड़ी हुई है। कोको आईलैंड में चीनी गुप्तचर पनडुब्बी भारतीय सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है। पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीस ने चीन की इस योजना का खुलासा 1998-99[7] में किया था। भारत की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रियात्मक कदम न उठाने पर चीन ने 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' के अंतर्गत श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार तक अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी।

- पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा विभिन्न नदियों की धाराओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि भारत की मुख्य नदियां तिब्बत से निकलकर भारत की सीमा में प्रवेश करती हैं। सिन्धु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियां दोनों देशों के बीच बहती हैं। 2005 में प्राचूलेक विवाद दोनों देशों के बीच विवाद का नया कारण बन गया। हिमाचल प्रदेश से करीब 35 कि.मी. दूर प्राचू

लेक का निर्माण हुआ है जो कि प्राचू नदी पर बनी है। इस विवाद पर तीखा प्रहार करते हुए चीन ने शेष नदियों के बहाव को तबाह करने की धमकी दी।[8] ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को चीन ने 12 नवंबर 2010 को रोका था। चीन जानगमु में 38 हजार मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजना तैयार कर रहा है।

- चीन-पाक संबंध की व्यापकता भारत-विरोधी आधार पर बनी है। चीन के नेता ने 2005 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान यह कहा था कि "चीन पाकिस्तान संबंध हिमालय से ऊँचे और समुद्र से भी गहरे हैं।" पाकिस्तान की परमाणु शक्ति चीन की ही भेंट है। भारत की सीमाओं पर हमला कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों में चीन निर्मित आधुनिक हथियार हैं।

- 2008 में चीन द्वारा घोषित आंकड़ों के अनुसार चीन का रक्षा पर खर्च तकरीबन 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। लेकिन सिप्री (स्टॉकहाम रिसर्च सेंटर) के अनुसार यह रकम 140 बिलियन डॉलर से ज्यादा है।

- माओ का मानना था कि अगर पूर्वी देश पश्चिमी देशों पर अपना दबदबा नहीं बना सकते तो बेहतर यही है कि पूर्व के शेष देशों पर अपना आधिपत्य कायम किया जाए। अर्थात् माओ की नीति शुरू से ही भारत विरोधी ही रही थी। जहां भारत साम्यवादी चीन को मान्यता देने वाला पहला देश था और संयुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर चीन की सदस्यता की तरफदारी करता रहा वहीं चीन भारत को कमजोर करने के किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देता है।

संदर्भ

1 विजय क्रांति, 'किस दिशा में चीन, 23 अक्टूबर 2010, अमर उजाला
2 दैनिक जागरण की रिपोर्ट, 'चीन के युवा शक्ति' 1 अक्टूबर 2010
3 अवधेश कुमार, 'चीन से सबक लेने का समय, 'दैनिक भास्कर' 27 सितंबर 2010
4 आशीष तिवारी, 'पाक और चीन का हर शहर निशाने पर' अमर उजाला, 25 अक्टूबर 2010
5 डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्टिंग, 'अरूणाचल में चीन की चाल' 24 अक्टूबर 2010
6 कानेजी फाउंडेशन की रिपोर्ट चीन पर - अक्टूबर 2010
7 भरत वर्मा, रक्षा विशेषज्ञ, "चीन से आक्रमण की आशंका" इंडियन डिफेंस रिव्यू-मई 2010
8 मोनिका चानसोरिया, "चीन का आधिपत्य तिब्बत में" सेंटर फॉर लैंड वार फेयर स्डीज, नई दिल्ली

अध्याय-पांच

नेहरू की अदूरदर्शिता और चीन की मनमानी

भारत चीन संबंधों को लेकर तिब्बत एक अहम मुद्दा रहा है और आगे भी रहेगा। तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर चीन की नीयत में हमेशा ही खोट रहा है। इसकी शुरुआत तभी हो चुकी थी जब चीन ने अपने ढ़ाई हजार साल पुराने एक राजनीतिक चिंतक झून-जी के सिद्धांत पर अमल करते हुए 1949 के बाद तिब्बत पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। 1950 में अंततः चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर ही लिया। इससे पहले भारत और चीन की सीमाएं आपस में नहीं मिलती थी क्योंकि दोनों राष्ट्रों के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में मौजूद था। 1950 में जब चीन की सेना तिब्बत में प्रवेश करने लगी तब जवाहरलाल नेहरू ने इसका शाब्दिक विरोध तो जरूर किया क्योंकि तब उन्हें यह भ्रम था कि चीन भारत के साथ रिश्ते खराब कर तिब्बत को हड़पने की कोशिश नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। चीन ने बड़े शातिराना अंदाज में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की दुहाई देते-देते तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन के तिब्बत पर कब्जे के साथ ही भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी हो गए और यहीं से शुरू हो गया अंतहीन सीमा विवाद।

यह शुरुआत केवल भारत के साथ टकराव की नहीं थी बल्कि इसके बाद तो चीन ने भारत के साथ ही पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मंगोलिया और इंडोनेशिया समेत एशिया के कई देशों पर नजरें गड़ानी शुरू कर दी थी। तिब्बत से तो भारत में भी घुसपैठ की राह आसान हो गई थी।

तिब्बत पर चीन का दावा तब और मजबूत हो गया जब नेहरू ने तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग मान लिया। इसके उपरांत ही चीन ने भारत-तिब्बत से जुड़े क्षेत्रों पर अपनी हकदारी शुरू कर दी। यहां पर नेहरू चीन की कुटिल चाल में बुरी तरह फंस गए। एक बार धोखा खाने के बाद भी

जवाहरलाल नेहरू की आँखें नहीं खुली। उन्हें दोबारा यह उम्मीद जगी कि शायद तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग मान लेने के बाद चीन भारतीय सुरक्षा लकीर को स्वीकार कर लेगा और तिब्बत की स्वायत्तता को भी मंजूर कर लेगा। हुआ ठीक इसके विपरीत। तिब्बत की स्वायत्तता तो दूर की बात रही, चीन तिब्बत को लेकर भारतीय राज्यों में भी अपने पैर पसारने लगा।

तिब्बत को हड़पने के उपरांत चीन ने भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ शुरू कर दी। चीन तकरीबन 38 हजार वर्ग कि.मी. का क्षेत्र अक्साई चीन के भीतर अपने कब्जे में लिए हुए है जो मुख्यतः लद्दाख का हिस्सा है।[1] 1963 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर का 5,180 वर्ग कि.मी. का पट्टा चीन को सुपूर्द कर दिया। पाकिस्तान की इस करवट से चीन की सामरिक स्थिति और मजबूत हो गई। अब चीन ने इस क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए सिक्यिांग और तिब्बत के बीच सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। काराकोरम हाईवे ने तिब्बत-कश्मीर-सिक्यिांग और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ लिया। दूसरी तरफ चीन ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सेंधमारी शुरू कर दी। तकरीबन 96,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर चीन अपनी दावेदारी पेश करने लगा। अर्थात संपूर्ण अरूणाचल प्रदेश चीन के दक्षिणी भूभाग के रूप में पेश किया गया। ये मांगें चीन तिब्बती संस्कृति और लिपि की आड़ में करने लगा। कई तिब्बती ग्रंथों में तिब्बत और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच एक सशक्त सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध की चर्चा है। चीन आज उन्हीं तिब्बती ग्रंथों को अपनी आधारभूत धरोहर मानकर भारतीय क्षेत्र को हड़पने की धमकी देता है। यह सब कुछ तिब्बत पर भारत की कमजोर नीति की वजह से हुआ है।

भारत को दबाव में रखने की गरज से ही हाल के वर्षों में चीन ने अपने सैनिक सिद्धांतों में बदलाव कर भारत की चिंता और बढ़ाई है। इन नीतियों में बदलाव के बाद अगर चीन को ऐसा लगे कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अक्षुण्णता को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह आक्रमण कर सकता है।[2] चीन का विवादास्पद आण्विक सिद्धांत भी भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। पहले आक्रमण नहीं करने की वचनबद्धता और "सक्रिय सुरक्षा" के बीच की सोच में बहुत गहरी खाई है, जिससे भारत-विरोधी धुंआ निकलता है। चीन के सैनिक सिद्धांत का एक पहलू यह भी है कि चीन दुश्मन देश की सीमा के भीतर घुसकर महत्वपूर्ण आर्थिक और सैनिक स्थलों को ध्वस्त करना चाहता है। पीएलए द्वारा प्रकाशित पत्र में इन बातों की गहन चर्चा है।

चीन द्वारा प्रकाशित सैनिक आलेख में इस बात पर भी चर्चा है कि चीन ताईवान, तिब्बत और अरूणाचल प्रदेश के मुद्दों पर आण्विक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।[3] ब्रिगेडियर वी. नायर ने चीन से उत्पन्न आण्विक शक्तियों पर चौकस रहने की चेतावनी दी है। नायर के शब्दों में, चूंकि चीन

का आण्विक सिद्धांत पूरी तरह से आक्रामक सोच पर टिका हुआ है, चीन का सैनिक सिद्धांत अरूणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अगर दोनों सिद्धांतों को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अरूणाचल प्रदेश को हथियाने में चीन आण्विक हथियारों का प्रयोग कर सकता है।[4]

चीन अमेरिका से प्रतिस्पर्द्धा में अपने आण्विक हथियारों को अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्रों से जोड़ना चाहता है। भारत का हर छोटा या बड़ा शहर चीन की प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता के भीतर है। हाल के वर्षों में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय दूरी के प्रक्षेपास्त्र पण्डुब्बियों में भी तैनात कर दिए है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन के पास करीब 240 से अधिक आण्विक बम हैं।[5] महत्वपूर्ण आण्विक प्रक्षेपास्त्रों की श्रंखला में डी.एफ-31, अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (आई.सी.बी.एम), डी.एफ.-4, डीएफ.-21 जैसे अनेकों प्रक्षेपास्त्र उसके पास है। उनमें से कई आण्विक प्रक्षेपास्त्र तिब्बत के पठारी ठिकानों पर तैनात हैं। ऊंचाई पर होने का फायदा चीन को 1962 के युद्ध में प्राप्त हुआ, जो आज भी कायम है।

संदर्भ

1 रिपोर्ट, तिब्बत डेली नवंबर, 2010

2 झिनुआ समाचार ब्यूरो की रिपोर्ट, 10 दिसंबर, 2008

3 बी.बी.सी. की रिपोर्ट, 15 अक्टूबर, 2007

4 जेनरल एस.के. सिन्हा “चीन को रोकने की जरूरत”, एशियन एज, 24 नवंबर, 2010

5 राहुल सिंह “चीन की सैन्य शक्ति को रोकना होगा”, टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 नवंबर 2010

अध्याय-छह

पर्यावरण की मार और घाटे का व्यापार

चीन का तिब्बत पर कब्जा करना भारत के लिए चौतरफा दबाव बनाने का पर्याय भी बना है। तिब्बत को हड़पने के साथ ही चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ भी शुरू कर दी। तिब्बत के बहाने भारत की सीमा में चीनी घुसपैठ न केवल राजनीतिक कारणों से की गई बल्कि इसका असर भारत के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल रूप से पड़ा है। वजह यह रही कि तिब्बत को चीन ने अपने आण्विक कचरे के भंडार के रूप में तब्दील कर दिया इसका असर तिब्बत से भारत की ओर आने वाली नदियों पर पड़ा और भारत का पर्यावरण भी दूषित हुआ।

हुआ यह कि चीन ने तिब्बत को न केवल सैनिक और आण्विक अड्डों में तब्दील कर दिया बल्कि उसने तिब्बत के महत्वपूर्ण हिस्सों को आण्विक कूड़ेदान की प्रयोगशाला बना दिया। चीन ने ऐसा करने के लिए तिब्बत के घने जंगलों को काटना शुरू किया। तकरीबन 2.5 मिलियन वर्ग कि.मी. में फैली तिब्बत की हरियाली और खूबसूरती चीन की राक्षसी नीतियों का शिकार बन गई। उल्लेखनीय है कि भारत के मैदानी ईलाकों में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ तिब्बत से निकल कर नेपाल के रास्ते भारत की ओर अपना उदगम बनाती है। ये नदियाँ हैं - ब्रह्मपुत्र, यांगसी और सतलज। न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे अन्य और देश भी हैं जहां तिब्बत से निकलने वाली नदियां बहती हैं। ये नदियां इन देशों की मेरुदण्ड हैं। ये न केवल पानी की कमी को पूरा करती है बल्कि उपजाऊ मिट्टी भी इनके बहाव के साथ मिलकर इन देशों की फसल को उपजाऊ बनाती है।

पिछले कई दशकों में तिब्बत की त्रासदी का इन देशों के मौसम पर प्रतिकूल असर हुआ है। विशेषकर भारत तो मौसम के मिजाज में आए बदलाव से बाढ़ के तांडव या भयंकर सूखे के संकट से जूझता

रहा है। एशिया की 85 प्रतिशत आबादी की जीवन शैली तिब्बत से बहने वाली नदियों से प्रभावित होती है। अगर चीन सैनिक समीकरण के नाम पर तिब्बत की पहाड़ियों पर बड़े-बड़े बांध बनवाता है तो भारत को प्रत्यक्ष नुकसान होगा। दूसरी तरफ तिब्बत के एक हिस्से को चीन द्वारा आण्विक अवशेष के कचरे में तब्दील कर देने से ये परमाणु-अवशिष्ट तत्व नदियों के मार्फत भारतीय खेत खलिहानों और लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं।

इस बर्बादी के पीछे भारत की ढुलमुल नीति और चीन की धूर्त मानसिकता है। तिब्बत के बहाने भारत के पर्यावरण को दूषित करने के साथ ही चीन ने बहुत ही सुविचारित नीति के तहत आपसी व्यापार के नाम पर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चौपट करने की पूरी तैयारी भी कर रखी है। दरअसल आपसी व्यापार के नाम पर चीन भारत जैसे विशाल बाजार पर कब्जा जमाना चाहता है जिसमें वह काफी हद तक सफल भी रहा है। सच बात यह है कि द्विपक्षीय व्यापार के नाम पर चीन अवैद्य तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में सेंध लगा रहा है।

अवैध व्यापार मुख्य रूप से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के जरिए हो रहा है। इन रास्तों से आ रहे सस्ते और आकर्षक चीनी उत्पादों से भारत के शहरों और गाँवों के बाजार पटे हुए हैं। पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही आते थे लेकिन अब बाजार में चाइनीज मोबाइल, सीडी प्लेयर, सीएफएल बल्ब, टीवी किट, मेमोरी चिप, आई सी क्वाइल, बिजली का बोर्ड, वायर और वाटर पंप बिक रहे हैं। मेड इन चाइना डालडा, साबुन, तौलिया, शैंपू, क्रीम, परफ्यूम, अंडर गारमेंट और सौंदर्य प्रसाधन भी उपलब्ध हैं। डिजिटल कैमरा और चीनी खिलौनों से तो दुकानें भरी हुई हैं। चीनी कपड़ों ने तो भारतीय कपड़ा कंपनियों की हालत पतली की हुई है। चाइनीज पोलिथीन भारतीय दुकानदार और ग्राहक दोनों की पहली पसंद है। आम उपभोक्ता इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत से अनजान होता है। सस्ता होने के कारण सभी इन्हें खरीदते भी हैं। सस्ता होने के साथ ही विविधतापूर्ण होने के कारण भी इनकी बिक्री ज्यादा होती है।

इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि आज भारत चीन के रास्ते अधिक जहरीले उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बन गया है। चीन ने अपने देश के लचीले श्रम कानून का फायदा उठाते हुए अपना सस्ता और घटिया सामान बाहर के देशों में पहुंचाना शुरू कर दिया और भारत इसका सबसे बड़ा बाजार बन गया है।

चीन भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नए-नए षड्यंत्र भी रचता रहता है। कभी नकली दवाएं बनाकर उन पर 'मेड इन इंडिया' का लेबल लगाकर बाजार में भेजना उसके इसी षड़यंत्र का

एक हिस्सा है। कुछ समय पहले मेड इन इंडिया की लेबल वाली नकली दवाओं की एक खेप नाइजीरिया में पकड़ी गई तो उस पर काफी बवाल भी मचा था।

अवैद्य व्यापार के साथ ही भारत चीन का वैध व्यापार भी बहुत तेजी से फल-फूल रहा है। दोनों देशों के बीच 2004 में 13.5 अरब डालर का व्यापार हुआ था जो बाद के वर्षों में 60 अरब डालर का हो गया। 2015 तक इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यापार में भारत को तो घाटा ही घाटा हो रहा है क्योंकि व्यापार बढ़ने के साथ भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ा है। 2002 में भारत और चीन के बीच का व्यापार घाटा 2 बिलियन डालर था जो बाद में बढ़कर 20 बिलियन डालर हो गया। इसके अलावा चीन भारत से औद्योगिक उत्पाद ही नहीं खरीदता वरन इस व्यापार में भारत की स्थिति किसी अफ्रीकी देश की तरह कच्चे माल के सप्लायर की है। भारत चीन को जो माल सप्लाई करता है उसमें से पचास फीसदी से ज्यादा तो लोहा ही होता है।

चीन की कई कंपनियां भारतीय व्यापारियों को अपने जाल में फंसाकर लाखों डॉलर की ठगी करने से भी गुरेज नहीं कर रही हैं। चीन में स्थित भारतीय दूतावास को बाकायदा पत्र लिखकर भारतीयों को इन कंपनियों की जालसाजी से निपटने के गुर बताने पड़े थे। कुछ समय पहले चीन स्थित भारतीय दूतावास में सचिव अभिषेक शुक्ला ने भारत के तमाम व्यापारिक संगठनों को पत्र लिखकर बताया था कि चीनी कंपनियों से व्यापार करते समय कौन-कौन-सी सावधानियां बरतनी चाहिए।

वर्ष 2009-10 में जहां चीनी कंपनियों द्वारा 78,43000 डॉलर की धोखाधड़ी की शिकायतें मिली वहीं वर्ष 2011-12 में नवंबर 2012 तक 54,34162 डॉलर की ठगी के मामले सामने आए हैं।

अध्याय-सात

पाक-चीन दोस्ती और अरूणाचल का संकट

अपने पड़ोसी देशों के साथ चीन के संबंधों का सबसे बड़ा खतरा भारत को चीन की पाकिस्तान के साथ हुई दोस्ती से माना जाता है और यही यथार्थ भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के साथ हुए 1962, 1965, 1971 और कारगिल के युद्धों को माना जाता है। इस लिहाज से चीन और पाकिस्तान को भारत का स्वाभाविक शत्रु भी माना जाता है। ये दोनों देश तथाकथित सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ बराबर की दूरी बनाए रखने के लिए पक्षधर हैं और इसी पक्षधरता के चलते एक-दूसरे के मित्र भी बन गए हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दशकों में चीन ने पाकिस्तान से मिले अपनत्व को आधार बनाते हुए अपनी कश्मीर नीति में बदलाव का संकेत देने के साथ ही भारतीय सुरक्षा में नए सिरे से सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। हिमालय के काराकोरम मुहाने पर चीन-पाक की संयुक्त घेराबंदी ने भारतीय सुरक्षा को घेर लिया है। इस गठबंधन को 'ची-पाक के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि इस घेराबंदी की ताकत आण्विक प्रक्षेपास्त्रों के बूते पर टिकी हुई है। चीन ने सामरिक चाल के जरिये पाकिस्तान को आण्विक हथियारों से पूरी तरह लैस कर दिया है।

पाक-चीन गठबंधन की शुरुआत शीत युद्ध के दौरान हुई। शीतयुद्ध के दौरान पाकिस्तान चीन संबंध की बुनियाद सामरिक समीकरणों के तहत बनी। पाकिस्तान 1971 के युद्ध में भारत से बुरी तरह परास्त होने के बाद एक ऐसे सहयोगी की खोज में था, जो उसकी भारत-विरोधी यात्रा में उसका साथ दे। इसी समीकरण के कारण चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के नजदीक आए। शुरुआती दौर में चीन ने कश्मीर को विवादास्पद मुद्दा बनाकर पाकिस्तान की नीति का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। चीन पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई सहजता से करने लगा। विदित है कि चीन का सीधा भूमिगत संपर्क दक्षिण एशिया के किसी देश से नहीं था लेकिन काराकोरम हाइवे बन जाने के बाद

दक्षिण एशिया और हिंद महासागर से उसका सीधा संपर्क कायम हो गया। इस मुहिम में चीन का दबदबा सियाचिन ग्लेशियर पर भी बनने लगा। सियाचिन कश्मीर मुद्दे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। सियाचिन भारत के जम्मू -कश्मीर राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। दूसरी तरफ सियाचिन से चीन की दक्षिणी सीमा मिलती है जहां से पूर्वी काराकोरम पहाड़ियां नजदीक हैं। यहीं पर अक्साई चीन भी मिलता है। 1985 में पाकिस्तान ने चीन को गिलगिट क्षेत्र में सैनिक छावनी बनाने की इजाजत दे दी। 1985 में चीन-पाकिस्तान ने मिलकर सियाचिन और नुब्राघाटी क्षेत्रों में संयुक्त सैनिक अभ्यास किया।

चीन ने हाल के वर्षों में सुनियोजित ढंग से भारतीय सीमाओं में अपनी सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। हिमालय के उत्तर में घुसपैठ के अलावा इसने तिब्बत के पठारी इलाकों में सुखोई-27 लड़ाकू विमानों और अत्याधुनिक सेनाओं के साथ जमीनी और हवाई सैन्य अभ्यास किया। चीन पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में उत्तर कोरिया का रूप देना चाहता है। उसने पाकिस्तान को कई तरह की मिसाइलों की आपूर्ति की है, जिनका मुख्य निशाना भारत है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान का अपना कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है, चीन का आदेश ही वहां लागू होता है। विश्व के अन्य देशों ने चीन के इस दोहरे चरित्र को अनदेखा किया है। अमेरिका स्थित संस्था साइंस एण्ड इन्टरनेशनल सिक्यूरिटी द्वारा लिए फोटोग्राफ से इस बात की पुख्ता जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद के जरिए खु शाब द्वितीय और खुश ााब तृतीय ऐटमी संयंत्रों का निमार्ण पूरा कर लिया है। पाकिस्तान के पास आज प्लूटोनियम बम तैयार है। एटोमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा आण्विक बम है। अत्याधुनिक प्लूटोनियम बमों को पाकिस्तान नए प्रक्षेपास्त्रों के सहारे भारत के किसी भी कोने में गिरा सकता है। पाकिस्तान की "फतेह जंग" मिसाईल इस्लामाबाद से महज 50 किमी. की दूरी पर है। वहीं पर शाहीन प्रथम और शाहीन द्वितीय प्रक्षेपास्त्रों का निमार्ण हुआ है। ये दोनो अन्तर्देश ाीय प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान को चीन की भेंट हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषक यह मानते हैं कि अगर चीन की मिलीभगत पाकिस्तान के साथ नहीं होती और पाकिस्तान ने पाक-अधिकृत कश्मीर का हिस्सा चीन को नही दिया होता तो शायद कश्मीर समस्या का हल खोज लिया जाता। पाकिस्तान के दिवंगत प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 17 जुलाई 1963 को पाकिस्तान के संसद में यह कहा था कि अगर कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के साथ युद्ध होता है तो चीन पाकिस्तान की हर संभव मदद करेगा तब पाकिस्तान की टिप्पणी के जवाबों में चीन के प्रधानमंत्री ने भी इसकी पुष्टि की थी। 1979 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की पेइचिंग यात्रा के दौरान चीन की मौलिक सोच में बुनियादी परिर्वतन दिखा।

एक विदेश मंत्री के रूप में बाजपेयी ने डेंश्ग्योपेंग को यह समझाने की कोशिश की कि कश्मीर मुद्दे पर चीन के अनावश्यक मतभेद से दोनो देशों के संबंध को चोट पहुंच रही है। इससे लाभ किसी को नही मिल रहा। बाजपेयी की स्पष्टवादिता ने डेंग की कश्मीर नीति बदली। चीन कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा मानने लगा और और इस बात की वकालत करने लगा कि कश्मीर का हल भारत और पाकिस्तान द्वारा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में ढूंढा जाना चाहिए। चीन की यह सोच तकरीबन तीन दशक तक कायम रही।

हाल के वर्षो में चीन की सोच में पुनः कटुता नजर आने लगी । चीन की वर्तमान व्यवस्था ने डेंग की बातों को भुलाकर कश्मीर विरोधी तेवर अपना रखा है। यही कारण था लद्दाख को चीन का हिस्सा मानना, इंटरनेट पर कश्मीर के नक्शे को तोड़ मरोड़ कर दिखाना और जम्मू-कश्मीर के लोगों को लूज पेपर वीजा देने की परंपरा शुरु करना।

सुरक्षा विशेषज्ञ भास्कर राव के अनुसार चीन ने पश्चिमी सीमा लद्दाख के नजदीक 'पागोंज तासो' में अपनी पहुंच बना ली है। चीन के सैनिक विस्तार से भारतीय सुरक्षा प्रबंधतंत्र चिंतित है।

लद्दाख का सीमाई क्षेत्र एक हाथ की मुट्ठी जैसा दिखता है, जिसके तीन महत्वपूर्ण हिस्से चीन के प्रभाव में हैं। चीन चौथे मुहाने को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है जिसे 'ट्रींग हाईट' के नाम से जाना जाता है। प्रो. कोंडापल्ली (प्रोफेसर जवहारलाल नेहरू विश्वविद्यालय) के अनुसार चीन के इस विस्तार से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वर्ष 2009 में जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को इस खतरे की सूचना थी। लेह में चीन की घुसपैठ की जानकारी थी। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है। अगर पश्चिमी मुहाने पर चीन की घुसपैठ को भारतीय सरकार नजरअंदाज करती रही तो जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल का रेंज भी चीन के कब्जे में आ जाएगा और भारत का पश्चिमी मुहाना पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगा। 22 दिसंबर 1959 को संसद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने चीन की हरकतों को देखते हुए यह कहा था कि "अक्साईचीन में चीन द्वारा बनाई जा रही सड़क का उपयोग सैन्यतंत्र के लिए होगा या आम लोगों की सुविधा के लिए, इस बात का फैसला कौन करेगा? दरअसल चीन की मानसिकता को देखते हुए इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसका प्रयोग सैन्य तंत्र के लिए ही होगा।" आज एक बार फिर से चीन भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रहा है। इसलिए उसने पाक-अधिकृत कश्मीर को जायज और भारत के हिस्से वाले असल कश्मीर को विवादास्पद मानकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कुल मिलाकर चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती भारत को बहुत भारी पड़ रही है और इसका असर उत्तर पूर्व के सीमांत राज्य अरूणाचल पर साफ देखा जा सकता है।

अरूणाचल को लेकर चीन की हरकतों को देखते हुए ऐसा लगता है कि चीन भारत के इस सीमांत राज्य को हड़प लेना चाहता है। वजह साफ है कि नवंबर 2006 में जब चीन के प्रधानमंत्री हू-जिंताओ भारत की यात्रा पर थे उसी दौरान भारत में चीन के राजदूत सन यूक्सी ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि पूरा का पूरा अरूणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, तवांग उसी हिस्से का एक अंग है, इसलिए उस पर पूरा अधिकार चीन का है। उसी दौरान चीन के एक सरकारी संस्था द्वारा प्रकाशित पत्र में यह कहा गया था कि चीन 1962 जैसी भूल नहीं करेगा। विजित इलाकों को लौटाया नहीं जाएगा। भारत को यह बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। विगत में चीन न केवल भारत के साथ बल्कि अन्य देशों के साथ युद्ध की महज संभावना से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर सैनिक अभ्यास किए गए है। मसलन 1950, 1962, 1969 और 1979 में ऐसे प्रयास चीन के द्वारा किया जा चुका है। ये सारे अभ्यास चीन द्वारा उस समय किए गए जब चीन सैनिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। आज तो चीन एक महाशक्ति का रूप ले चुका है। चीन की चाल का अंदाजा एक ऑनलाईन मैपिंग से भी होता है। यह ऑनलाईन सरकारी तंत्र का हिस्सा है। यह ऑनलाईन गूगल के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा किया गया। ऑनलाईन चीनी भाषा में है जिसके पाठक 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश ा को चीन का भाग दिखाया गया है। इस मानचित्र में दक्षिण हिस्से को गौण मानकार उत्तर-पूर्वी हिस्सा आसाम तक को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। कश्मीर के अक्साई चीन के हिस्से को चीन के उत्तर पश्चिम अंग के रूप में दिखाया गया है। यह सब कुछ चीन की साम्यवादी सरकार के सर्वे और मानचित्र विभाग ने तैयार किया है। अरूणाचल प्रदेश ा की कुल सीमा तकरीबन 90,000 वर्ग किमी. की है जिसमें चीन 83,743 किमी. तक के हिस्से पर अपना पुश्तैनी अधिकार मानता है। इस पूरे उपक्रम ने मैकमहोन लाईन और वास्तविक सीमा रेखा की मान्यता पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि चीन शुरू से ही मैकमहोन लाईन को मानने से इंकार करता रहा है जबकि भारत इस लाईन को आज भी भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानता है।

चीन अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय गुप्तचर संस्थाओं की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि चीन उत्तर पूर्वी राज्यों में तैनात भारतीय समीकरण की तैयारी की पूरी जानकारी अलगाववादी तत्व चीन तक पहुंचाते हैं। ऐसा होने से चीन को हर भारतीय पहल की जानकारी रहती है। हाल ही में नागालैंड का अलगाववादी संगठन नागालीम के नेता एथोंनी को जब नेपाल में पकड़ा गया तो उसने यह बात कबूल की कि कैसे चीन को भारतीय सैन्य समीकरण की पूरी जानकारी रहती है। चीन के एक सरकारी थिंक टैंक ने एक पत्र प्रकाशित कर भारत को कई खंडों में तोड़ने की मंशा जाहिर की है।

चीन का मानना है कि भारतीय संघ पूरी तरह से बालू की भीत पर टिका हुआ है। महज एक धक्का देने से बालू की भीत कई खंडों में टूट कर बिखर जाएगा।

रक्षा विश्लेषक भारत वर्मा कहते हैं कि माओ ने तिब्बत को लेकर 1949 में ही कहा था कि हिमालय के तटवर्ती इलाके दांत की तरह है जिनके बंद हो जाने से जिह्वा सुरक्षित रहता है अन्यथा बाहरी शक्तियों की घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहेगा।

अध्याय-आठ

नेपाल पर भी लगी है चीन की नजर

अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन न केवल भारत-नेपाल के रिश्ते को तोड़ देना चाहता है बल्कि उसकी नीयत मौका देखकर भारत के कुछ सीमांत क्षेत्रों के साथ ही नेपाल को भी हड़प लेने की है। इसी सोच के तहत उसकी नजरें नेपाल पर भी लगी हुई हैं। गौरतलब है कि नेपाल, चीन और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ब्रिटिश राज में नेपाल का सामरिक कद उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। परिवर्तित परिस्थितियों में नेपाल की अहमियत बढ़ गई है। नेपाल के भीतर बदल रहे राजनीतिक रंग ने चीन की भूमिका को और विशिष्ट बना दिया है। नेपाल के माओवादी घटक चीन की मदद से सत्ता हड़पने की फिराक में रहते हैं। कुछ महीने पहले चीन द्वारा नेपाली सांसदों की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश हुआ। चीन की इस पहल ने भारतीय सुरक्षा के लिए नई चिंता पैदा कर दी है। चिंता के और कई कारण हैं। इनमें प्रमुख कारण इस प्रकार हैं।

● चीन तिब्बत के दूसरे महत्वपूर्ण शहर झिज्जे से नियाग्जी को रेल लाईन से जोड़ने की योजना बना रहा है। यह क्षेत्र भारत-नेपाल सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। चीन की रेल परियोजना काठमांडू तक ले जाने की है। 2009 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीन की रेल लाईन काठमांडू तक ले जाने की बात कही थी। चीन पहले से ही तिब्बत को नेपाल के एक शहर सयाब्रूवेसी तक जोड़ना चाहता है इस पर 17 कि.मी. लम्बी सड़क निमार्ण का काम काफी पहले ही शुरू कर चुका है। अगर यह सड़क योजना पूरी कर ली जाती है तो बीजिंग और दिल्ली के बीच की यात्रा मोटरगाड़ी से की जा सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह बदलाव तो बड़ा लुभावना लगता है लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसी सुविधाओं का प्रयोग चीन मुख्यतः अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ही करता रहा है। इसलिए भविष्य में यह भारतीय सुरक्षा के लिए एक कठिन चुनौती होगी।

● इंटरनेशनल कैम्पेन फौर तिब्बत ने 2009 की अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा किया था कि चीन की पकड़ नेपाल की राजनीति में तेजी से फैल रही है। चीन के इशारे पर नेपाल तिब्बतियों के साथ बदसलूकी कर रहा है। कई प्रदर्शनकारियों को जेल के भीतर डाल दिया गया है। चिंता का कारण यह है कि चीन नेपाल में घुसपैठिए की तरह अपना रास्ता बना रहा है।

● माओ की सामरिक सोच में पांच उँगलियां ही भारत और चीन के बीच 'बफर स्टेट' के रूप में होनी चाहिए। नेपाल के रास्ते से तिब्बत तक पहुंचने की डगर सबसे सुलभ और सुविधाजनक है। चीन की नजरों में भारत का नेपाल से विशेष संबंध, तिब्बत की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए चीन ने तिब्बत को हड़पने के उपरांत ही नेपाल में अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। चीन के नेताओं ने खुलेआम यह कहना शुरू कर दिया कि संघर्ष की स्थिति में नेपाल अकेले नहीं होगा।

● चीन की नेपाल नीति मुख्यतः हस्तक्षेपवादी है। चीन ने नेपाल में अपनी नीतियों का अनुसरण अपने द्वारा निर्देशित उन शोध संस्थाओं की अनुशंसा पर किया है, जो नेपाल के विभिन्न शहरों में स्थापित किए गए हैं। 50 से ज्यादा ऐसे संस्थान बटवाल, बानेपा, सनखुवासभा, पोरवरा, विराटनगर, मोरंग, सुनसारी, चितवन, नेपालगंज और लुंबनी में काम कर रहे हैं। साउथ एशिया के भूतल निर्देशक भीम सिंह के अनुसार 31 से ज्यादा चीनी अध्ययन संस्थान नेपाल के दक्षिणी हिस्से में हैं जहां पर भारत-नेपाल की सीमा मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय रेडियो ने नेपाल में एफ. एम. रेडियो की शुरूआत की। इस रेडियो प्रोग्राम का मकसद भी चीन की पकड़ को नेपाल में स्थापित करना है। यह सब नेपाल स्थित चीनी दूतावास के निर्देशन में किया जा रहा है। 2005 में चीन-नेपाल सहयोग संस्था की शुरूआत की गई। चीन बहुमुखी परियोजनाओं द्वारा नेपाल की भारत-निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता है।

● 2007 से लेकर आजतक चीन के दो दर्जन से ज्यादा उच्च अधिकारी नेपाल की यात्रा पर आ चुके हैं। जिसमें चीन के मेजर जनरल और तिब्बत के उप कमांडेट की गुप्त वार्ता भी शामिल है। चीन नेपाल में सैनिक मदद के जरिए भारत विरोधी तेवर को हवा दे रहा है।

उल्लेखनीय है कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिन्ताओ की पकड़ वहां के अन्य नेताओं से कहीं ज्यादा रही है। क्योंकि वह राष्ट्रपति पद के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी रहे हैं। सेना पर भी उनकी पकड़ है। वे राष्ट्रपति बनने के पहले तिब्बत के गर्वनर थे। आज जो चीन की नीतियों में भारत-विरोधी भावना का प्रसार हुआ है वह जिन्ताओ की ही देन है। एक ओर चीन भारत के साथ मित्रवत संबंध बनाकर अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सामरिक

रणनीतियों को भी मजबूत इरादों के साथ नई उंचाइयों पर ले जाना चाहता है।

अटल बिहारी बाजपेयी ने चीन के वास्तविक चेहरे से नकाब उठाते हुए 22 दिसम्बर 1959 को संसद में प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को सचेत करते हुए ये शब्द कहे थे, "चीन की नीति आक्रामक और विस्तारवादी दृष्टिकोण से जुडी हुई है। हमारे रक्षामंत्री ने यह कहकर देश को भूल भूलैया में डाल दिया है कि भारत और चीन के संबंध दो हजार वर्ष पुराने सांस्कृतिक आयाम से जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री चीन के हमले और प्रसार से सशंकित हैं। ऐसे माहौल में हम किसका भरोसा करें? रक्षा मंत्री का या प्रधानमंत्री का? लेकिन मैं यहां पर जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि जिन 2000 वर्षों की बात हमारे रक्षामंत्री कह रहे हैं वे बातें पुरानी हो चुकी हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। साम्यवादी चीन ने उन सारे मूल्यों और तथ्यों को मिटा दिया है, जिसे चीनी इतिहासकार या पर्यटक बुद्ध की मिसाल लेकर भारत-चीन के बीच एक सांस्कृतिक आयाम की अलख जगाना चाहते हैं। ह्वेनसांग और फाहियान की बातें कब्र में दफनाई जा चुकी हैं। नया साम्यवादी चीन एक भूखे भेड़िए की तरह आक्रामक मूड में है। वह परिस्थितियों के अनुरूप गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है। लेकिन उसका मौलिक रूप हस्तक्षेप और आक्रमण के जरिए अपने सामरिक विस्तार को फैलाना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ वर्षों में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को कैसे आगे बढ़ाया है? मंचूरिया जो 1911 तक चीन पर शासन करता था, उसका नामो निशान मिटा दिया गया। वह अब चीन के उत्तर-पूर्वी राज्य का हिस्सा बनकर रह गया है। पूर्वी तुर्किस्तान मूलतः सिक्यिांग बन गया है। मंगोलिया के आधे से अधिक हिस्से को चीन में मिला लिया गया है। तिब्बत जो भारतीय सुरक्षा के लिए अहम हिस्सा हुआ करता था, वह भी चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार बन चुका है। चीन का अपना मूलभूत क्षेत्रफल केवल 14 लाख वर्ग मील तक सीमित था लेकिन आज चीन की सीमा 22 लाख वर्ग मील तक फैल चुकी है। यह सब कुछ मंचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत, कांसू, चिंघाई और सिक्यिांग को हड़पने से बनी है। अब इसकी गिद्ध दृष्टि भारत के 48 हजार वर्ग मील क्षेत्र पर टिकी हुई है। एक बौद्ध भिक्षु ने इस बात का खुलासा किया है कि चीन तिब्बत को हाथ का तलहटी समझता है जिसकी पांच अंगुलियां हैं। ये अंगुलियां लद्दाख, भूटान, सिक्किम, नेपाल और आसाम हैं। अगर समय रहते चीन की इस नीति को चुनौती नहीं दी गई तो भविष्य में हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।"

चीन के पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा ने भारत की चिंता को और बढ़ा दिया। पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर चीन के अतिक्रमण ने और संदेह की स्थिति और संदेहास्पद बना दी। चीन अपनी कुटिलता से आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की आड़ में सामरिक विस्तार को ढंकना चाहता है। साथ ही चीन आर्थिक रूप से भारत को एक अदना सहयोगी भर बनाने की पूरी कोशि ाश कर

रहा है। उल्लेखनीय है कि द्विपक्षीय व्यापार में भारत 19 अरब डॉलर का घाटा उठा रहा है। चीन की संरक्षणवादी नीतियां इसकी जड़ में हैं। 2009-10 में कुल 42.4 अरब का व्यापार हुआ जिसमें चीन का निर्यात 30.8 अरब डॉलर एवं भारत का केवल 11.6 अरब डॉलर हुआ।

अध्याय-नौ

इतिहास के संदर्भ में भारत-चीन संबंधों की प्रमुख घटनाएं

- मार्च 1948- चयांग काईसेक ने भारत में आयोजित एशियन रिलेशन कांफ्रेंस में तिब्बती प्रतिनिधि मंडल का घोर विरोध किया।
- मार्च 1948 - भारत ने अमेरिकी दबाव के विरूद्ध चीन को लामबद्ध करने की नीति का विरोध किया।
- 30 दिसंबर 1949 - भारत बर्मा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण गैर साम्यवादी देश बना जिसने साम्यवादी चीन को मान्यता दी।
- नवंबर 1950 - भारत ने अमेरिकी नीति का विरोध किया जिसमें कोरिया विवाद के अंतर्गत चीन को दोषी माना गया था।
- नवंबर 1950 - नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को शामिल करने की वकालत की।
- मार्च 1955 - भारत ने चीन के मानचित्र में नेफा के हिस्सों को दर्शाने का विरोध किया।
- 23 जनवरी 1959 - चीन के प्रधानमंत्री ने पहली बार यह कहा कि लद्दाख और नेफा में तकरीबन 40,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर चीन का हक है।
- 3 अप्रैल 1959 - दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत की शरण में आ गए।
- 7 सितंबर 1959 - नेहरूजी ने चीन के खतरे को लेकर संसद में प्रथम श्वेत पत्र जारी किया।
- 25 अप्रैल 1960- चीन ने भारत द्वारा तैयार की गई सीमा रिपोर्ट को मानने से इंकार कर दिया।
- 1962- भारत-चीन युद्ध जिसमें चीन ने भारत के आक्साईचीन को अपने कब्जे में कर लिया।
- 2 सितंबर 1962 - चीन की सेना यागला क्षेत्र में भारतीय सीमा के दो कि.मी. भीतर तक घुस आई।
- 18 नवंबर 1962 - चीन की सेना ने बोमडीला और नेफा क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया।

- 23 मार्च 1963 - तिब्बत के पठार पर चीन ने अपनी सेना की अतिरिक्त टुकड़ी को तैनात किया। इस बदलाव से भारतीय सुरक्षा खतरे में आई।
- सितंबर 1965 - चीन ने भारत-पाक युद्ध (1965) के दौरान खुल्लम-खुल्ला पाकिस्तान का समर्थन किया और युद्ध के लिए भारत को दोषी माना।
- 1967- सिक्किम में भारत-चीन झड़प, जो मुख्यतः नाथु-ला और चा-ला घटानाओं के लिए प्रसिद्ध थी।
- मई 1974 - भारत के शांतिपूर्ण आण्विक परीक्षण की चीन ने जमकर भर्त्सना की।
- 1986-87 - अरूणाचल प्रदेश में चीन और भारत के बीच झड़प हुई।
- 1988 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा और शांति सदभावना के माहौल में सीमा विवाद का हल।
- 1993- पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्ह राव और लीपेंग के बीच वार्ता और सीमा विवाद पर समझौता।
- 1998 - भारत का आण्विक विस्फोट।
- मई 1998 - पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस ने चीन को दुश्मन नम्बर-1 माना।
- जून 1998 - चीन ने की भाारत से आण्विक बम न बनाने की अपील।
- अगस्त 1999- चीन ने उस भारतीय अपील को ठुकरा दिया जिसमें यह कहा गया था कि चीन लद्दाख में सड़कों का जाल बिछा रहा है और भारतीय सीमा के भीतर अतिक्रमण कर रहा है।
- जनवरी 2000 - चीन की सेना ने भारतीय सीमा के भीतर घुसकर लद्दाख और अक्साईचीन में बंकर का निर्माण किया।
- जून 2003- पूर्व प्रधानमंत्री बाजपेयी की चीन यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश। सीमा व्यापार के तहत सिक्किम और तिब्बत के बीच आने-जाने की अनुमति
- 2004 - दोनों देशों द्वारा सिक्किम में नाथू-ला और जेलेप-ला मुहानों को खोलने की आजादी। ऐसा करना दोनों देशों के हित में माना गया।
- अप्रैल 2005 - चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा। दोनों देशों द्वारा सहयोग और सामरिक मुद्दों पर बातचीत।
- नवंबर 2006 - चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ की भारत यात्रा। दोनों देशों के बीच 10 महत्वपूर्ण सामरिक मसलों पर आम सहमति।
- जनवरी 2007 - चीन ने की अंतरिक्ष हमले की तैयारी। चीन ने अंतरिक्ष में 537 कि.मी. मौसम की जानकारियों के लिए काम कर रहे अंतरिक्ष पर हमला। पूरी दुनिया चीन के

कारनामों से अचंभित रह गई। पेंटागन ने चीन की आक्रामक नीतियों को दुनिया के लिए खतरनाक माना।

- 13 जनवरी 2008 - भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चीन यात्रा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनी आम सहमति
- जून 2008 - चीन की सेना द्वारा भारतीय सीमा सिक्किम में घुसपैठ और पुनः वापस जाना। सिक्किम का यह क्षेत्र फिंगर एरिया के रूप में जाना जाता है। चीन इस क्षेत्र में तकरीबन 2.1 कि.मी. जो उत्तरी सिक्किम का हिस्सा है, चीन उसे अपना क्षेत्र मानता है।
- मार्च 2009 - चीन ने अरूणाचल प्रदेश के विकास के लिए एशियन विकास बैंक की लोन राशि को रोकने की कोशिश की।
- अगस्त 2009 - चीनी वायु सेना के दो हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हुए लेह के चुनार एरिया में खाद्य पदार्थ ड्राप करते हुए दिखाई दिए।
- अगस्त 2009 - भारत और चीन की सेना के बीच सिक्किम में झड़प।
- सितंबर 2009 - चीन की सेना तकरीबन 1.5 किमी भीतर तक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई।
- सितंबर 2009 - दलाई लामा की आध्यात्मिक यात्रा पर चीन का विरोध।
- अक्टूबर 2009- जम्मू-कश्मीर के लोगों को लूज पेपर वीजा दिया जाना।
- अक्टूबर 2009 - चीन ने मनमोहन सिंह की अरूणाचल प्रदेश यात्रा का विरोध किया। पूर्व विदेश सचिव ने चीन विरोध को गलत और अनैतिक करार दिया।
- नवंबर 2009 - चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बांध बनाने की पुष्टि।
- अप्रैल 2010 - भारतीय गृहमंत्री की तबांग यात्रा।
- सितंबर 2010 - भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन की उस नीति को खतरनाक माना जिसके तहत भारत को दक्षिण एशिया में घेरने की कोशिश की जा रही है।
- अक्टूबर 2010 - भारतीय सेना प्रमुख ने चीन की चाल को भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया।
- अक्टूबर 2010 - पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने संसद में चीन के मंसूबों को अत्यंत ही खतरनाक मानते हुए यह कहा कि चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है।
- दिसंबर 2010 - चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा व्यापार पर समझौता, सीमा विवाद पर आश्चर्यजनक चुप्पी।
- जनवरी 2011 - चीन की सेना का वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन गोबीर गांव में एक

यात्री शेड का निर्माण रूकवा दिया गया।

- अप्रैल 2011 - चीन ने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री से सैन्य सहयोग का वादा किया और नत्थी वीजा को खत्म करने की बात कही।
- नवंबर 2011- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चीनी राष्ट्रपति वेन जिया बाओ ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर करने में सहयोग की बात की।
- 23 मार्च, 2012 - इस तरह की खबरें थीं कि चीनी इंजिनियर्स ने पाक अधिÑत कश्मीर में सड़क, संचार के साधन और भवनों का निर्माण किया गया था जिसे चीन ने नकार दिया था कि एलओसी के उस पार चीन की उपस्थिति है।
- अगस्त 2012 - चीन के वाणिज्य मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और संयुक्त आर्थिक दल की मीटिंग में सम्मिलित हुए थे।
- नवंबर 2012 - आर्थिक और रणनीति विषयों पर दूसरे दौर की चर्चा हुई और चार एमओयूज सरकारों के बीच और सात व्यावसायिक एमओयूज पर दस्तखत हुए। जिनकी कीमत 5.2 बिलियन डॉलर थी।
- दिसंबर 2012 - ऱाट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन की यात्रा पर थे और उन्होंने सीमा विवाद पर अनौपचारिक वार्ता की।
- जनवरी 2013 - पांचवीं वार्षिक सुरक्षा वार्ता बीजिंग में संपन्न हुई
- मार्च 2013 - भारत और चीन ने सीमा विवाद पर एक बार फिर चर्चा की। चीन लगातार पाक अधिÑत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और पीओके का जो हिस्सा उसने चीन को सुपूर्द किया है उसे और अरूणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दक्षिणी तिब्बत बताता रहा है।
- 15 अप्रैल, 2013 - इस तरह की खबरें आईं कि चीनी सैनिक दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र के भारतीय सीमा में 19 कि.मी. अंदर तक आ गए थे। 2010-12 के बीच में 600 से अधिक सीमा अतिक्रमण की घटनाएं भारतीय सीमा क्षेत्र में एलएसी के पार हो चुकी हैं।
- 5 मई, 2013 - भारत और चीन के बीच इस बात की सहमति बनी थी कि चीनी सेना दौलत बेग ओल्डी से पीछे हट जाएगी।
- 9 मई, 2013 - भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चीन की यात्रा पर वहां के विदेश मंत्री यांग ई के आमंत्रण पर गए और द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
- 19 मई, 2013 - चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने भारत और चीन के बीच लम्बे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए जोर दिया।